facebook.com/ thebharatshri
twitter.com/ thebharatshri
website thebharatshri

राष्ट्र को एक सूत्र में बांधते हैं हम

भारत श्री

राष्ट्रीय हिंदी साप्ताहिक

सोमवार, 27 अप्रैल 2026 ● वर्ष 7 ● अंक 41 ● मूल्यः 5 रुपए

अमेरिका और रूस के बीच...

सद्गुरु वाणी

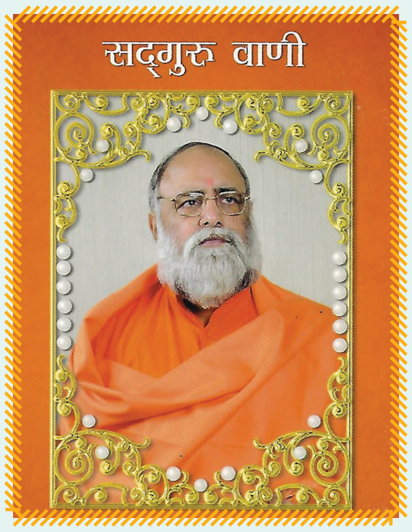

विश्व भर में होने वाले प्रभु कृपा दुख निवारण समागम केवल प्रभु की कृपा से संभव होते हैं। इसका आयोजन कोई व्यक्ति नहीं करता।

●

परमात्मा की नजर में सभी भाई-बहन बराबर हैं। परमात्मा जाति, धर्म, देश, सम्प्रदाय से पार है। हमें सभी भाई-बहनों को समान दृष्टि से देखना चाहिए।

●

दिव्य पाठ प्रभु कृपा का वह आलोक है जिसे करने के लिए किसी भी प्रकार की कठिन तपस्या या साधना की कोई जरूरत नहीं है। यह बड़ा सहज और सरल है।

कृपा वचन

ईश्वर सबको रास्ते देता है, फर्क बस इतना है- कोई विश्वास से चलता है, कोई सवालों में रुक जाता है।

●

सत्य की सबसे बड़ी खासियत यह है कि उसे याद नहीं रखना पड़ता।

●

जब मन शांत होता है, तब ईश्वर शब्दों में नहीं, अनुभूति में बोलता है।

ईरान-अमेरिका तनाव के बीच पाकिस्तान की भूमिका पर सवाल

अमेरिका की शर्तों के चलते शांति वार्ता पर सहमति नहीं

ईरान-अमेरिका तनाव के बीच कूटनीतिक कोशिशें तेज, पाकिस्तान की भूमिका पर उठे सवाल और होर्मुज को लेकर वैश्विक चिंता गहराई

@ भारतश्री ब्यूरो

मध्य-पूर्व में जारी तनाव एक बार फिर वैश्विक राजनीति के केंद्र में आ गया है। ईरान और अमेरिका के बीच चल रही कूटनीतिक खींचतान अब केवल दो देशों तक सीमित नहीं रह गई, बल्कि इसमें पाकिस्तान, रूस, यूरोप और खाड़ी देशों की भूमिकाएं भी चर्चा का विषय बन गई हैं। ताज़ा घटनाक्रम में ईरान ने जहां पाकिस्तान की मध्यस्थता पर सवाल उठाए हैं, वहीं अमेरिका की ओर से कड़ी चेतावनियां और यूरोपीय संघ का सख्त रुख इस पूरे मामले को और जटिल बना रहा है।

पाकिस्तान की मध्यस्थता पर ईरान का संदेह

ईरानी संसद की राष्ट्रीय सुरक्षा और विदेश नीति समिति के प्रवक्ता इब्राहिम रेजई ने पाकिस्तान की भूमिका पर स्पष्ट रूप से असहमति जताई है। उनका कहना है कि पाकिस्तान भले ही एक मित्र देश हो, लेकिन वह निष्पक्ष मध्यस्थ की भूमिका निभाने में सक्षम नहीं है। रेजई के अनुसार, पाकिस्तान अक्सर अमेरिकी हितों के अनुरूप अपनी नीतियां बनाता है और खुलकर अमेरिका के खिलाफ बयान देने से बचता है।

यह बयान उस समय सामने आया जब ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघची ने 24 घंटे के भीतर दो बार पाकिस्तान का दौरा किया। इन दौरों का उद्देश्य ईरान और अमेरिका के बीच वार्ता को आगे बढ़ाना था, लेकिन ठोस परिणाम सामने नहीं आ सके।

ट्रम्प की चेतावनी और ऊर्जा संकट की आशंका

इस बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने ईरान को कड़ी चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि यदि ईरान तीन दिनों के भीतर युद्धविराम के लिए सहमत नहीं होता, तो उसकी तेल पाइपलाइनों को गंभीर नुकसान हो सकता है। ट्रम्प के अनुसार, यदि तेल निर्यात बाधित होता है, तो पाइपलाइनों में दबाव बढ़ेगा और तकनीकी कारणों से विस्फोट की स्थिति उत्पन्न हो सकती है।ऊर्जा विशेषज्ञों का मानना है कि यदि ऐसा होता है, तो न केवल ईरान की अर्थव्यवस्था प्रभावित होगी बल्कि वैश्विक तेल बाजार में भी भारी उथल-पुथल देखने को मिल सकती है।

- पाकिस्तान की मध्यस्थता पर ईरान ने निष्पक्षता को लेकर सवाल उठाए
- ट्रम्प ने ईरान को सीजफायर के लिए तीन दिन की चेतावनी दी
- होर्मुज स्ट्रेट बना वैश्विक तनाव का सबसे बड़ा केंद्र
- ईरान के प्रस्ताव से वैश्विक शेयर बाजारों में आई तेजी

यूरोपीय संघ का सख्त रुख

यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयेन ने स्पष्ट किया है कि ईरान पर लगे प्रतिबंधों को हटाना अभी जल्दबाजी होगी। जर्मनी की राजधानी बर्लिन में आयोजित एक बैठक में उन्होंने कहा कि ये प्रतिबंध ईरान सरकार द्वारा अपनी ही जनता पर किए गए दमन के कारण लगाए गए थे।

उनका मानना है कि जब तक ईरान के भीतर ठोस बदलाव नहीं दिखते, तब तक प्रतिबंधों को हटाना उचित नहीं होगा। यह बयान पश्चिमी देशों के सामूहिक रुख को दर्शाता है, जो ईरान पर दबाव बनाए रखना चाहते हैं।

वार्ता विफल होने के पीछे अमेरिका की शर्तें

ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघची ने अमेरिका पर आरोप लगाया है कि उसकी "अत्यधिक मांगों" के कारण शांति वार्ता सफल नहीं हो सकी। उन्होंने बताया कि इस्लामाबाद में हुई बातचीत में आगे की रणनीति तय करने की कोशिश की गई थी, लेकिन सहमति नहीं बन पाई।अराघची ने यह भी संकेत दिया कि ईरान फिलहाल अपने रणनीतिक हितों से पीछे हटने को तैयार नहीं है। विशेष रूप से होर्मुज जलडमरूमध्य और परमाणु कार्यक्रम को लेकर उसका रुख सख्त बना हुआ है।

तनाव के बीच समझौते का संकेत

होर्मुज जलडमरूमध्य, जो वैश्विक तेल आपूर्ति का एक बड़ा मार्ग है, इस समय कूटनीतिक तनाव का मुख्य केंद्र बना हुआ है। ईरान ने इस क्षेत्र को लेकर अपनी स्थिति स्पष्ट करते हुए इसे रेड लाइन बताया है।हालांकि, रिपोर्ट्स के अनुसार ईरान ने अमेरिका को एक प्रस्ताव दिया है जिसमें होर्मुज को दोबारा खोलने की बात कही गई है, लेकिन इसके बदले परमाणु मुद्दे पर बातचीत को बाद के लिए टालने का सुझाव दिया गया है। यह प्रस्ताव तत्काल संकट को कम करने की दिशा में एक व्यावहारिक कदम माना जा रहा है।

MN DIVINE
ORDER ALL TYPES OF :
• POOJA SAMAGRI,
• AYURVEDIC MEDICINE
• AND PRATIMA.
NOW GET AT YOUR HOME ON
MNDIVINE.COM
ORDER NOW
https://mndivine.com/
HELPLINE : 9667793986
(10AM TO 6PM, MON-SAT)

अनधिकृत कॉलोनियों के नियमितीकरण से 45 लाख लोगों को राहत

दिल्ली में आवास अधिकारों की दिशा में बड़ा कदम

@ अभिषेक चौबे

राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में लंबे समय से चली आ रही अनधिकृत कॉलोनियों की समस्या के समाधान की दिशा में एक अहम पहल शुरू हो गई है। दिल्ली सरकार ने इन कॉलोनियों के नियमितीकरण की प्रक्रिया को औपचारिक रूप से आगे बढ़ाते हुए लाखों परिवारों को उनके घरों पर वैधानिक अधिकार देने की दिशा में ठोस कदम उठाया है।

इस निर्णय से राजधानी के लगभग 45 लाख लोगों को सीधा लाभ मिलने की उम्मीद है, जो वर्षों से अपने ही घरों में कानूनी मान्यता के अभाव में असुरक्षा का सामना कर रहे थे।दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने एक प्रेस वार्ता के दौरान इस योजना की विस्तृत जानकारी साझा करते हुए इसे राजधानी के लिए "राहत, सम्मान और अधिकार" का नया अध्याय बताया। उन्होंने कहा कि यह केवल एक प्रशासनिक प्रक्रिया नहीं, बल्कि उन परिवारों के लिए न्याय का क्षण है, जो दशकों से अपने ही घर में मालिकाना हक के लिए संघर्ष कर रहे थे।

वर्षों पुरानी समस्या का समाधान

दिल्ली में अनधिकृत कॉलोनियों का मुद्दा नया नहीं है। पिछले कई दशकों में तेजी से हुए शहरीकरण, बढ़ती आबादी और आवास की कमी के कारण बड़ी संख्या में कॉलोनियां बिना औपचारिक अनुमति के विकसित हुईं। इन कॉलोनियों में रहने वाले लोग बिजली-पानी जैसी मूलभूत सुविधाएं तो किसी तरह प्राप्त कर लेते थे, लेकिन कानूनी स्वामित्व के अभाव में उन्हें कई समस्याओं का सामना करना पड़ता था-जैसे संपत्ति की खरीद-बिक्री में बाधा, बैंक लोन की अनुपलब्धता और सरकारी योजनाओं का लाभ न मिल पाना।

इस पृष्ठभूमि में केंद्र सरकार की पीएम उदय योजना को लागू किया गया था, जिसका उद्देश्य इन कॉलोनियों को नियमित करना और निवासियों को मालिकाना अधिकार देना था। अब इस योजना को नई गति देते हुए राज्य और केंद्र सरकार ने मिलकर प्रक्रिया को सरल और समयबद्ध बनाने का प्रयास किया है।

1511 कॉलोनियों में प्रक्रिया शुरू

मुख्यमंत्री ने बताया कि कुल 1731 अनधिकृत कॉलोनियों में से 1511 कॉलोनियों के नियमितीकरण की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। यह अपने आप में एक बड़ा प्रशासनिक कदम है, क्योंकि इतने बड़े स्तर पर एक साथ प्रक्रिया शुरू करना कई विभागों के समन्वय की मांग करता है।उन्होंने कहा कि वर्षों से लंबित इस मुद्दे को अब प्राथमिकता के आधार पर हल किया जा रहा है, ताकि अधिक से अधिक लोगों को जल्द से जल्द राहत मिल सके।

45 दिन में मालिकाना हक

इस योजना की सबसे खास बात इसकी समयसीमा है। सरकार ने पूरी प्रक्रिया को स्पष्ट चरणों में विभाजित किया है, ताकि अनावश्यक देरी और भ्रष्टाचार की संभावनाओं को कम किया जा सके।

यह समयबद्ध ढांचा सुनिश्चित करता है कि आवेदकों को लंबा इंतजार न करना पड़े और उन्हें जल्द से जल्द कानूनी अधिकार मिल सकें।

22 बाधाओं को किया गया खत्म

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बताया कि इस प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए केंद्र और राज्य सरकार ने मिलकर 22 प्रमुख बाधाओं को समाप्त किया है। पहले जहां दस्तावेजों की जटिलता, तकनीकी अड़चनें और विभागीय देरी बड़ी समस्या थीं, वहीं अब इन सभी को व्यवस्थित कर प्रक्रिया को आसान बनाया गया है।

यह सुधार विशेष रूप से उन लोगों के लिए महत्वपूर्ण है, जो सीमित संसाधनों के कारण जटिल प्रक्रियाओं को पूरा करने में असमर्थ रहते थे।

छोटे व्यापारियों को भी राहतइस योजना के तहत केवल आवासीय संपत्तियों को ही नहीं, बल्कि छोटे व्यापारियों को भी राहत देने का प्रयास किया गया है। सरकार ने 20 वर्गमीटर तक की दुकानों को भी कुछ शर्तों के साथ नियमित करने का प्रावधान किया है।

ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट पर जोर

सरकार ने इस पहल को केवल नियमितीकरण तक सीमित नहीं रखा है, बल्कि भविष्य के शहरी विकास को भी ध्यान में रखा है। इसी क्रम में ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट नीति को आगे बढ़ाया जा रहा है।इस नीति के तहत मेट्रो और आरआरटीएस कॉरिडोर के आसपास 500 मीटर के दायरे में लगभग 207 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में योजनाबद्ध विकास किया जाएगा। इसमें उच्च घनत्व (हाई-डेंसिटी) और मिश्रित उपयोग (मिक्स्ड यूज) वाले प्रोजेक्ट्स को बढ़ावा दिया जाएगा।

गरीब और मध्यम वर्ग को मिलेगा लाभ

सरकार का मानना है कि इस पूरी पहल का सबसे बड़ा लाभ गरीब और मध्यम वर्ग के परिवारों को मिलेगा। नियमितीकरण के बाद इन परिवारों को अपने घरों पर कानूनी अधिकार मिलेगा, जिससे वे बैंक लोन ले सकेंगे, संपत्ति का हस्तांतरण कर सकेंगे और सरकारी योजनाओं का लाभ उठा सकेंगे।इसके अलावा, संपत्ति का वैल्यू भी बढ़ेगा, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार होने की संभावना है।

केंद्र सरकार को दिया श्रेय

मुख्यमंत्री ने इस योजना का श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देते हुए कहा कि यह उनके विजन का परिणाम है, जिसमें हर नागरिक को सम्मानजनक आवास देने की बात की गई है।

उन्होंने केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर का भी आभार जताया, जिन्होंने इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई डिजिटल और पारदर्शी प्रक्रियासरकार ने इस पूरी प्रक्रिया को डिजिटल बनाने पर भी जोर दिया है, ताकि पारदर्शिता बनी रहे और लोगों को बार-बार सरकारी दफ्तरों के चक्कर न लगाने पड़ें।

चुनौतियां भी आएंगी सामने

हालांकि यह पहल महत्वपूर्ण है, लेकिन इसके सामने कई चुनौतियां भी हैं। इतने बड़े स्तर पर नियमितीकरण की प्रक्रिया को लागू करना आसान नहीं है। जमीन के स्वामित्व, दस्तावेजों की सत्यता और तकनीकी मुद्दों को सुलझाना एक जटिल कार्य है।विशेषज्ञों का मानना है कि यदि इस प्रक्रिया को पारदर्शी और निष्पक्ष तरीके से लागू किया गया, तो यह देश के अन्य शहरों के लिए भी एक मॉडल बन सकता है।

सस्पेंड DIG भुल्लर के 11 ठिकानों पर ED की दबिश

भ्रष्टाचार मामले में गिरफ्तार पंजाब पुलिस के सस्पेंड डीआईजी हरचरण सिंह भुल्लर की मुश्किलें और बढ़ गई हैं। सोमवार को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने उनके चंडीगढ़ स्थित आवास पर दबिश दी। ईडी मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम (PMLA), 2002 के तहत भुल्लर और अन्य के मामले में सर्च ऑपरेशन चला रही है। इस दौरान इनोवा कार से ईडी ने एक बैग और कागजी दस्तावेज बरामद किए हैं।ईडी द्वारा PMLA की धारा 17 के तहत कुल 11 ठिकानों पर तलाशी ली जा रही है। इनमें चंडीगढ़ (2), लुधियाना (5), पटियाला (2), नाभा (1) और जालंधर (1) शामिल हैं। ये सभी ठिकाने आरोपी, उसके सहयोगियों और संदिग्ध बेनामी व्यक्तियों से जुड़े बताए जा रहे हैं।

AAP के 7 सांसदों को BJP में विलय की मंजूरी

राज्यसभा के सभापति सीपी राधाकृष्णन ने सोमवार को आम आदमी पार्टी (AAP) के सात बागी सांसदों के भाजपा में विलय को मंजूरी दे दी है। इस फैसले के बाद राज्यसभा में AAP की संख्या घटकर 3 रह गई है, जबकि BJP सांसदों की संख्या 106 से बढ़कर 113 हो गई है।जो सात सांसद BJP में शामिल हुए हैं, उनमें राघव चड्ढा, अशोक मित्तल, हरभजन सिंह, संदीप पाठक, विक्रमजीत साहनी, स्वाति मालीवाल और राजेंद्र गुप्ता शामिल हैं। राज्यसभा की ऑफिशियल वेबसाइट पर भी इन सांसदों को BJP के सदस्यों के रूप में दिखाया गया है।

दिल्ली में IRS अफसर की बेटी का रेप-मर्डर

दिल्ली के पॉश इलाके कैलाश हिल्स में बुधवार सुबह आयकर विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी की 22 वर्षीय बेटी की घर में घुसकर हत्या कर दी गई। आरोपी ने उसके साथ दुष्कर्म किया, फिर मोबाइल फोन चार्जिंग केबल से गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी।घटना के वक्त वह घर में अकेली थी। माता-पिता जिम गए थे। पुलिस ने इस मामले में 19 वर्षीय घरेलू सहायक राहुल मीणा को गिरफ्तार किया है।

राघव चड्ढा का बड़ा सियासी पलटवार

AAP छोड़ BJP में शामिल, टॉक्सिक माहौल और भटके मकसद का लगाया आरोप

@ रिंकू विश्वकर्मा

भारतीय राजनीति में एक बड़े घटनाक्रम के तहत राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा ने आम आदमी पार्टी को छोड़कर भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया है। पार्टी बदलने के बाद जारी अपने पहले वीडियो संदेश में चड्ढा ने आम आदमी पार्टी के अंदरूनी माहौल पर गंभीर सवाल उठाए हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि पार्टी अब अपने मूल उद्देश्यों से भटक चुकी है और कुछ भ्रष्ट व समझौता करने वाले लोगों के हाथों में सिमट गई है।

'AAP अब वैसी पार्टी नहीं रही'

चड्ढा ने अपने बयान में कहा कि उन्होंने राजनीति में आने से पहले एक सफल चार्टर्ड अकाउंटेंट के रूप में करियर बनाया था, लेकिन देश सेवा के उद्देश्य से उसे छोड़ दिया। उन्होंने कहा, मैं AAP का संस्थापक सदस्य रहा हूं और अपने जीवन के 15 साल इस पार्टी को दिए हैं। लेकिन आज यह वह पार्टी नहीं रही, जिसके लिए हमने संघर्ष किया था।उन्होंने यह भी जोड़ा कि पार्टी में अब काम करने की स्वतंत्रता नहीं बची है और विचार रखने तक पर रोक लगाई जाती है।

टॉक्सिक वर्क एनवायरनमेंट का आरोप

चड्ढा ने AAP पर सबसे बड़ा आरोप उसके कार्यसंस्कृति को लेकर लगाया। उनके मुताबिक, पार्टी के भीतर टॉक्सिक वर्क एनवायरनमेंट बन चुका है, जहां न केवल काम करने में बाधाएं हैं, बल्कि संसद में बोलने तक से रोका जाता है।उन्होंने कहा जब किसी संगठन में आपकी आवाज दबा दी जाए, मेहनत को नजरअंदाज किया जाए और आपको चुप रहने के लिए मजबूर किया जाए, तो वहां काम करना मुश्किल हो जाता है।

सात सांसदों के एक साथ जाने का सवाल

चड्ढा ने इस बात पर भी जोर दिया कि वह अकेले नहीं हैं जिन्होंने पार्टी छोड़ी है। उनके साथ कुल सात राज्यसभा सांसदों ने AAP से दूरी बनाई है। उन्होंने सवाल उठाते हुए कहा, "एक व्यक्ति गलत हो सकता है, दो भी हो सकते हैं, लेकिन क्या सात लोग एक साथ गलत हो सकते हैं?

AAP छोड़ने वालों में अशोक मित्तल, विक्रमजीत साहनी, हरभजन सिंह, संदीप पाठक, स्वाति मालीवाल और राजिंदर गुप्ता शामिल बताए जा रहे हैं।

राज्यसभा में बदला समीकरण

राजनीतिक घटनाक्रम के बीच राज्यसभा में इन सांसदों के BJP में विलय को मंजूरी मिल गई है। इसके बाद उच्च सदन में BJP की संख्या बढ़कर 113 हो गई है, जो उसे और मजबूत स्थिति में ले जाती है।यह बदलाव न केवल संसद के समीकरण को प्रभावित करता है, बल्कि आगामी विधायी फैसलों पर भी असर डाल सकता है।

तीन विकल्प और एक फैसला

चड्ढा ने अपने निर्णय को लेकर स्पष्ट किया कि उनके सामने तीन विकल्प थे-राजनीति छोड़ देना, पार्टी में रहकर सुधार की कोशिश करना या किसी अन्य दल के साथ जुड़कर सकारात्मक राजनीति करना।उन्होंने कहा, मैंने तीसरा रास्ता चुना। मेरा मानना है कि अगर आप बदलाव नहीं ला सकते, तो उस व्यवस्था का हिस्सा बने रहना भी उचित नहीं है।

कार्यस्थल का उदाहरण देकर समझाया निर्णय

अपने फैसले को आम लोगों तक सरल तरीके से समझाने के लिए चड्ढा ने कार्यस्थल का उदाहरण दिया। उन्होंने कहा, अगर किसी ऑफिस का माहौल खराब हो जाए, जहां आपको काम करने से रोका जाए और आपकी मेहनत को दबाया जाए, तो वहां टिकना मुश्किल होता है। ऐसे में सही निर्णय होता है उस जगह को छोड़ देना।

'जनता के मुद्दे उठाता रहूंगा'

BJP में शामिल होने के बाद भी चड्ढा ने यह भरोसा दिलाया कि वह पहले की तरह जनता के मुद्दों को उठाते रहेंगे। उन्होंने कहा कि अब वह केवल समस्याएं नहीं उठाएंगे, बल्कि उनके समाधान भी तलाशने की कोशिश करेंगे। AAP छोड़ने वाले नेताओं की सुरक्षा को लेकर भी राजनीतिक खींचतान सामने आई है। पंजाब सरकार ने हरभजन सिंह की Y कैटेगरी सुरक्षा हटा ली, जिसके बाद केंद्र सरकार ने उन्हें CRPF सुरक्षा प्रदान कर दी।

सिक्किम के स्वर्णिम उत्सव में प्रधानमंत्री का दौरा

विकास परियोजनाओं के साथ ऐतिहासिक जुड़ाव का संदेश

@ रिंकू विश्वकर्मा

उत्तर-पूर्व भारत के सामरिक और सांस्कृतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण राज्य सिक्किम इन दिनों अपने 50वें स्थापना वर्ष का जश्न मना रहा है। इस विशेष अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दो दिवसीय दौरे पर सोमवार को राजधानी गंगटोक पहुंचे। उनके आगमन के साथ ही शहर में उत्साह का माहौल देखने को मिला। लिबिंग हेलिपैड से लोक भवन (राज्यपाल आवास) तक उनका रोड शो आयोजित किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में लोग सड़कों पर उमड़ पड़े।प्रधानमंत्री का यह दौरा न केवल राज्य के स्थापना दिवस समारोह के समापन से जुड़ा है, बल्कि इसके माध्यम से केंद्र सरकार द्वारा पूर्वोत्तर क्षेत्र में विकास और कनेक्टिविटी को लेकर प्रतिबद्धता का भी संकेत मिलता है।

4 हजार करोड़ की परियोजनाओं की सौगात

अपने दौरे के दौरान प्रधानमंत्री लगभग 4,000 करोड़ से अधिक की विकास परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे। ये परियोजनाएं शिक्षा, स्वास्थ्य, बुनियादी ढांचा, पर्यटन, पर्यावरण और कृषि जैसे विभिन्न क्षेत्रों से संबंधित हैं।स्वास्थ्य क्षेत्र में नामची में 100 बेड का आधुनिक अस्पताल और देओराली में 30 बेड का अस्पताल बनाया जाएगा। इन परियोजनाओं का उद्देश्य राज्य के दूरदराज इलाकों तक बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाना है। इन्फ्रास्ट्रक्चर के तहत तीस्ता नदी पर दो डबल-लेन स्टील पुलों का निर्माण प्रस्तावित है, जिससे राज्य के भीतर और बाहरी क्षेत्रों के साथ संपर्क मजबूत होगा।

स्थापना दिवस समारोह का समापन

16 मई 2025 को सिक्किम को भारत का हिस्सा बने 50 वर्ष पूरे हुए थे। इस अवसर पर वर्षभर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए। प्रधानमंत्री उस समय वर्चुअल माध्यम से समारोह में शामिल हुए थे। अब मंगलवार को इन आयोजनों का औपचारिक समापन होगा, जिसमें प्रधानमंत्री की उपस्थिति इसे विशेष बना रही है। राज्य सरकार के अनुसार, यह आयोजन केवल एक उत्सव नहीं, बल्कि सिक्किम की ऐतिहासिक यात्रा और विकास की उपलब्धियों को याद करने का अवसर है।

रणनीतिक दृष्टि से अहम राज्य

सिक्किम का महत्व केवल एक सुंदर पर्यटन स्थल के रूप में नहीं है, बल्कि यह भारत की सुरक्षा और रणनीतिक दृष्टि से भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। चीन, नेपाल और भूटान से सटे इस राज्य की भौगोलिक स्थिति इसे संवेदनशील बनाती है।1967 में नाथू-ला संघर्ष के दौरान चीनी सेना ने सिक्किम क्षेत्र में घुसपैठ की कोशिश की थी, जिसे भारतीय सेना ने सफलतापूर्वक विफल कर दिया।

सिक्किम का भारत में विलय की प्रक्रिया

सिक्किम का भारत में विलय एक लंबी और जटिल राजनीतिक प्रक्रिया का परिणाम था। 1947 में भारत की स्वतंत्रता के समय तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू सिक्किम के साथ भूटान की तरह एक विशेष संबंध स्थापित करना चाहते थे।1950 में भारत और सिक्किम के बीच एक शांति समझौता हुआ, जिसके तहत सिक्किम को भारत का संरक्षित राज्य बनाया गया। इस समझौते के तहत भारत को सिक्किम की रक्षा और विदेश नीति की जिम्मेदारी सौंपी गई।1970 के दशक में सिक्किम के भीतर राजनीतिक अस्थिरता बढ़ने लगी। तत्कालीन चोग्याल पाल्डेन थोंडुप नामग्याल स्वतंत्र पहचान बनाए रखने के पक्ष में थे, जबकि जनता का एक बड़ा वर्ग भारत में पूर्ण विलय चाहता था।1973 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने स्थिति को संभालने के लिए खुफिया एजेंसी रॉ के प्रमुख आर. एन. काओ को जिम्मेदारी सौंपी।

यूपी बोर्ड रिजल्ट 2026: रिकॉर्ड पास प्रतिशत, लेकिन पढ़ाई की असली तस्वीर क्या है?

2026 का रिजल्ट: लड़कियां फिर चमकीं, पास प्रतिशत ने बनाया इतिहास

इस साल 23 अप्रैल 2026 को यूपी बोर्ड ने 10वीं और 12वीं का रिजल्ट घोषित कर दिया। कुल 52 लाख से ज्यादा छात्र-छात्राओं ने रजिस्ट्रेशन कराया था। 10वीं में 27.5 लाख से ज्यादा बच्चे शामिल हुए और 90.42 प्रतिशत पास हो गए। यह सामान्य परीक्षा में बोर्ड के 103 साल के इतिहास का सबसे ऊंचा पास प्रतिशत है।

लड़कियों ने लड़कों को पीछे छोड़ दिया। लड़कियों का पास प्रतिशत 93.76 रहा जबकि लड़कों का 87.30। 12वीं में 24.8 लाख छात्र शामिल हुए और 80.38 प्रतिशत पास हुए। यहां भी लड़कियां आगे रहीं, उनका पास प्रतिशत 86.32 जबकि लड़कों का 75.04। बोर्ड अधिकारियों ने बताया कि परीक्षा फरवरी-मार्च में हुई थी और उत्तर पुस्तिकाओं की जांच ठीक से हुई। टॉपर्स में काशिश वर्मा, अंशिका वर्मा जैसी लड़कियां 10वीं में और शिखा वर्मा 12वीं में आगे रहीं। यह रिजल्ट देखकर माता-पिता और शिक्षक खुश हैं लेकिन कई सवाल भी उठ रहे हैं कि क्या सिर्फ पास प्रतिशत बढ़ने से शिक्षा बेहतर हो गई है।

पिछले साल 2025 में 10वीं का पास प्रतिशत 90.11 था और 12वीं का 81.15। इस बार भी लगभग वैसा ही है लेकिन 10वीं में थोड़ा सुधार हुआ। बोर्ड ने कहा कि सरकारी स्कूलों में सुविधाएं बढ़ने से नतीजे अच्छे आए। अब बच्चे घर बैठे रिजल्ट चेक कर रहे हैं और आगे की पढ़ाई की योजना बना रहे हैं।

दशकों में पास प्रतिशत का सफर: 14 प्रतिशत से 90 प्रतिशत तक

पिछले कुछ दशकों में यूपी बोर्ड की पढ़ाई और रिजल्ट में काफी बदलाव आया है। 1992 में 10वीं का पास प्रतिशत सिर्फ 14.70 था। उस समय लड़कों का 8.47 और लड़कियों का 36.44 था। तब स्कूल कम थे, शिक्षक कम थे और बच्चे पढ़ने के लिए दूर-दूर जाते थे। 2010 के आसपास पास प्रतिशत 60-70 के बीच रहता था। लेकिन 2020 के बाद सुधार दिखने लगा। 2020 में 83.31, 2022 में 88.18, 2023 में 89.78, 2024 में 89.55 और 2025 में 90.11 प्रतिशत तक पहुंच गया। 12वीं में भी 70 प्रतिशत से बढ़कर 80 प्रतिशत के करीब हो गया।

2021 में कोविड के कारण बिना परीक्षा के रिजल्ट 97-99 प्रतिशत तक चला गया था लेकिन वह सामान्य नहीं माना जाता। अब 2026 में 10वीं का 90.42 प्रतिशत सामान्य परीक्षा में सबसे अच्छा है। यह बदलाव सरकार की योजनाओं की वजह से हुआ। स्कूलों में स्मार्ट क्लासरूम बने, मिड-डे मील बेहतर हुआ और लड़कियों को पढ़ाने के लिए अलग-अलग स्कीम चलाई गईं। पास प्रतिशत बढ़ने से बच्चे कॉलेज जा पा रहे हैं और नौकरी के सपने देख रहे हैं। लेकिन कुछ शिक्षक कहते हैं कि पास प्रतिशत बढ़ाने के लिए कभी-कभी पेपर आसान कर दिए जाते हैं। फिर भी कुल मिलाकर पिछले 30-40 साल में बोर्ड की पढ़ाई मजबूत हुई है। बच्चे अब ज्यादा तैयार होकर आते हैं।

छात्र संख्या बढ़ी या घटी: नामांकन की पूरी कहानी

यूपी बोर्ड में बच्चे बढ़े हैं या घटे, यह देखना दिलचस्प है। 1990 के दशक में 10वीं में करीब 17-18 लाख बच्चे शामिल होते थे। अब 2026 में 27.5 लाख से ज्यादा। 12वीं में भी 25 लाख के करीब। यानी पिछले तीन दशकों में संख्या करीब 50 प्रतिशत बढ़ गई। इसके पीछे आबादी बढ़ना और सरकारी प्रयास हैं। सरकारी स्कूलों में नामांकन बढ़ाने के लिए शारदा कार्यक्रम, आरटीई और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसी योजनाएं चलीं। ड्रॉपआउट कम हुए। लेकिन हाल के कुछ सालों में कुल स्कूल नामांकन में थोड़ी गिरावट आई। 2021-22 में कुल 4.68 करोड़ बच्चे स्कूलों में थे जो 2024-25 तक 4.14 करोड़ रह गए। यानी 53 लाख बच्चे कम हो गए। इसमें प्राइवेट स्कूलों की ओर शिफ्ट और कुछ ड्रॉपआउट भी शामिल हैं। फिर भी 10वीं और 12वीं में बोर्ड स्तर पर संख्या स्थिर या बढ़ी है। सेकेंडरी क्लास में नामांकन का हिस्सा बढ़ा है। इसका मतलब है कि प्राथमिक स्तर से बच्चे आगे बढ़ रहे हैं। शहरों और गांवों दोनों में स्कूल पहुंच आसान हुई। लेकिन ग्रामीण इलाकों में अभी भी कुछ बच्चे काम पर लग जाते हैं। कुल मिलाकर बच्चे बढ़े हैं लेकिन गुणवत्ता बनाए रखना चुनौती है। बोर्ड के आंकड़े दिखाते हैं कि संस्थागत छात्र ज्यादा पास होते हैं जबकि प्राइवेट उम्मीदवार कम। यानी सरकारी और स्कूल आधारित पढ़ाई मजबूत हो रही है।

शहरों में शिक्षा की स्थिति: सुविधाएं बढ़ीं लेकिन दबाव भी

शहरों जैसे लखनऊ, कानपुर, गाजियाबाद और इलाहाबाद में यूपी बोर्ड की पढ़ाई की तस्वीर थोड़ी अलग है। यहां स्मार्ट क्लासरूम, कंप्यूटर लैब और अच्छे शिक्षक ज्यादा हैं। 2700 से ज्यादा स्मार्ट क्लासरूम शहरों के सरकारी स्कूलों में लगाए गए। इससे नामांकन और उपस्थिति बढ़ी। बच्चे डिजिटल तरीके से पढ़ रहे हैं जो पहले सिर्फ प्राइवेट स्कूलों में होता था। शहरों में प्राइवेट स्कूल भी ज्यादा हैं लेकिन यूपी बोर्ड वाले स्कूलों में गरीब और मध्यम वर्ग के बच्चे पढ़ते हैं। पास प्रतिशत शहरों में अक्सर राज्य औसत से ऊपर रहता है क्योंकि यहां ट्यूशन, कोचिंग और अतिरिक्त क्लास आसान हैं। लेकिन दबाव भी ज्यादा है।

बच्चे 10वीं-12वीं में प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं। परिवारों की उम्मीदें ऊंची हैं। शहरों में लड़कियों की पढ़ाई और बेहतर है क्योंकि सुरक्षा और सुविधाएं अच्छी हैं। फिर भी कुछ चुनौतियां बाकी हैं। जैसे क्लास में बच्चे ज्यादा होने से व्यक्तिगत ध्यान कम मिलता है। कई शहरों में यूपी बोर्ड के स्कूल पुराने हैं लेकिन अब उन्हें अपग्रेड किया जा रहा है। कुल मिलाकर शहरों में स्थिति ग्रामीण इलाकों से बेहतर है लेकिन असली गुणवत्ता अभी भी परीक्षा नंबरों से परे है। बच्चे कितना समझ रहे हैं, यह सोचने की बात है।

पढ़ाई की गुणवत्ता: रिजल्ट अच्छे लेकिन सीखने का स्तर सुधारा जाए

रिजल्ट अच्छे आने से खुशी है लेकिन पढ़ाई की गुणवत्ता पर सवाल भी हैं। पिछले दशकों में स्कूलों की संख्या बढ़ी, इमारतें बनीं और शिक्षक ट्रेनिंग हुई। मिशन प्रेरणा जैसे कार्यक्रमों से पढ़ने-लिखने का स्तर सुधरा। लेकिन कई रिपोर्ट्स कहती हैं कि बच्चे रट्टा मारकर पास हो जाते हैं।

असली समझ कम है। शहरों में कोचिंग कल्चर ज्यादा है जो रिजल्ट सुधारता है लेकिन समग्र विकास नहीं। गांवों में अभी भी बुनियादी सुविधाएं कम हैं। हाल के वर्षों में नामांकन प्राइवेट स्कूलों की ओर शिफ्ट हुआ। इसका मतलब है कि सरकारी स्कूलों को और मजबूत करना होगा। सरकार ने स्मार्ट क्लास और डिजिटल टूल्स लगाए लेकिन शिक्षकों की कमी और बड़ी क्लास साइज समस्या बनी हुई है।

लड़कियों का प्रदर्शन अच्छा है जो समाज के लिए अच्छा संकेत है। लेकिन नौकरी बाजार में स्किल की जरूरत है। बोर्ड रिजल्ट सिर्फ एक पड़ाव है। असली सफलता तब होगी जब बच्चे सोचने, समझने और समस्या हल करने में सक्षम होंगे। यूपी बोर्ड की यात्रा सकारात्मक है लेकिन अभी और मेहनत की जरूरत है। माता-पिता, शिक्षक और सरकार मिलकर काम करें तो आने वाले दशक में और बेहतर नतीजे दिखेंगे।

राष्ट्रीय हिंदी साप्ताहिक
भारत श्री
राष्ट्र को एक सूत्र में बांधते हैं हम
सोमवार, 27 अप्रैल 2026 , विक्रम संवत 2080

समुद्र समान संघ

संघ की तुलना एक ऐसे समुद्र से की जाती है जो सभी जीवों को अंतिम शांति देता है सभी अंत में उसी में समाहित होते हैं। लेकिन समुद्र का पानी हमेशा खारा होता है वह किसी जीव के उपयोग में नहीं आता। इसी तरह संघ का भी चरित्र है। संघ में जो भी शामिल होता है वह संघ से कुछ प्राप्त करने की इच्छा नहीं रखता संघ को देता ही है और यदि कोई सन्घ से कुछ प्राप्त करना चाहता है तो वह निराश ही होता है क्योंकि संघ एक समुद्र है। सन्घ अपना जल भाप बनकर सब जीवों को आवश्यकता अनुसार पहुंचाता है लेकिन संघ किसी दाता को किसी तरह का लाभ नहीं देता। यही कारण है कि संघ को अब तक ब्राह्मणों की पार्टी माना जाता था ऐसा माना जाता था कि संघ पर ब्राह्मणों का वर्चस्व है लेकिन जब कुछ ब्राह्मण जो संघ से कुछ प्राप्त करना चाहते थे उन्हें उस समय झटका लगा जब सन्घ ने उन संगठित ब्राह्मणों को कोई विशेष रियायत देने से इनकार कर दिया क्योंकि संघ सर्वजाती सर्वधर्म सर्व मानव समूह का एक संगठन है किसी जाति के लिए नहीं। आज यह बात सिद्ध हो गई है कि संघ अपने मूल स्वभाव के अनुसार समुद्र के समान है और उसकी परीक्षा लेने वाले ब्राह्मण संगठन फेल हो गए हैं। मैं संघ की इस परीक्षा के पास करने में संघ का नमन करता हूं । संघ को एक समुद्र के समान ही भारी रहना चाहिए क्योंकि सर्वजाती सर्वधर्म सर्व मानव समूह को संघ से बहुत उम्मीदें हैं। कुछ तथा कथित स्वार्थी ब्राह्मण अब कब मिनिस्टरों के साथ मुसलमान के साथ देशद्रोहियों के साथ तालमेल कर रहे हैं इससे हम भले ही बंगाल चुनाव हार जाएं इससे भले ही देश की सरकार चली जाए लेकिन हमारा स्वभाव नहीं बदलना चाहिए संघ सरकार के लिए नहीं समाज के लिए है। समुद्र को कभी धमकियों से विचलित नहीं होना चाहिए। हमें पूरे समाज की योग्यता पर भरोसा करना चाहिए कुछ मुट्ठी भर स्वार्थी लोग हमें अपने उचित मार्ग से विचलित नहीं कर सकते।

ज्ञानेंद्र आर्य

लोकतंत्र का मतलब बस भाजपा या कांग्रेस नहीं!!

@ **नितिन ठाकुर**

आज जब राघव चड्ढा झोला उठाकर कई सांसदों को लेकर भाजपा के विलय आंदोलन का अंग बन गए तब कुछ बातें कहना ज़रूरी है। हां, फर्क कुछ नहीं पड़ता मगर अपनी तरफ से लिख देना चाहिए। तीसरा राजनीतिक विकल्प बनने का दावा पेश कर रही आम आदमी पार्टी के प्रति मेरा कोई निजी रुझान शेष नहीं, पर इस प्रयोग की संभावित विफलता को भाजपा कांग्रेस की सफलता बताने का अवसर खोज रहे समर्थकों के सामने कुछ बातें मुझे लिखनी हैं। मेरे कुछ पॉइंट्स हैं, आप चाहे जवाब लिख सकते हैं, मैं पढ़ूंगा।

बीजेपी- कांग्रेस दोनों दलों के कट्टर समर्थकों ने आज राजनीति को एक खेल बना दिया है। भाजपा समर्थक को लगता है कि उनके दल के बाहर सब राष्ट्रविरोधी हैं, और कांग्रेस समर्थक को लगता है कि उनके बिना लोकतंत्र अंधकार में है। यह रवैया वैचारिक कट्टरता का चरम है। समर्थक भूल जाते हैं कि जब विकल्प केवल दो होते हैं, तो पार्टियां जनता के प्रति जवाबदेह होने के बजाय केवल एक दूसरे की कमियां गिनाकर चुनाव जीतती हैं। इसे राजनीति विज्ञान में 'नेगेटिव पार्टिसनशिप' कहा जाता है, जहाँ आप अपनी पसंद को वोट नहीं देते, बल्कि दूसरे की नफरत में वोट देते हैं। भारत जैसे विशाल, विस्तृत और विविधतापूर्ण देश में जो लोग बस भाजपा या कांग्रेस के अस्तित्व को ही अपरिहार्य मानते हैं, वो दरअसल लोकतंत्र के उपभोक्ता तो हो सकते हैं, पर उसके रक्षक नहीं। लोकतंत्र का मूल मंत्र बहुलतावाद है, जबकि दो दलीय व्यवस्था अनिवार्य रूप से वैचारिक विकल्पों को बाइनरी में सीमित कर देती है।

भाजपा और कांग्रेस दोनों का केंद्रीय ढांचा अक्सर राजनीतिक वर्चस्व यानी राजनीतिक वर्चस्व की तलाश में रहता है। द्वि-दलीय प्रणाली के पैरोकार तर्क देते हैं कि इससे "स्थिरता" आती है। लेकिन क्या ये सो कॉल्ड स्थिरता क्षेत्रीय पहचानों के विलोपन की ओर नहीं बढ़ रही? तमिलनाडु की द्रविड़ राजनीति, ओडिशा का अस्मिता-वाद या उत्तर-पूर्व की जनजातीय चिंताएं इन दोनों राष्ट्रीय दलों के दिल्ली-केंद्रित विमर्श में केवल एक सांख्यिकीय डेटा बनकर रह जाती हैं। पिछले दिनों जब मैं असम और मेघालय पहुंचा तो सिविल सोसायटी में इसे लेकर भारी शिकायत देखी। मुझे यकीन है बंगाल भी इसे महसूस करता होगा। वो लोग इन दलों को दिल्ली संचालित मानते हैं, और सिर्फ नई दिल्ली भारत नहीं है।दोनों दलों के कैडर आज इको चैंबर्स में जी रहे हैं। यहाँ विमर्श का स्तर तथ्य से गिरकर ट्रोलिंग तक आ गया है। हालांकि आज के सियासी हालात में बचा इससे कोई भी नहीं। भाजपा समर्थक अक्सर संगठनात्मक अनुशासन के नाम पर कन्फर्मिटी का शिकार हैं, जहाँ नेतृत्व पर सवाल उठाना वर्जित है।कांग्रेस समर्थक अक्सर एक खास विरासत के नॉस्टैल्जिया में कैद हैं, जो नए और उभरते हुए विकल्पों को 'वोट कटुआ' कहकर खारिज कर देते हैं। ये समर्थक समझने में विफल हैं कि लोकतंत्र किसी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की फ्रेंचाइजी नहीं है।

अगर कोई देश की राजनीति में टीएमसी, वामपंथी दलों, समाजवादी पार्टी, बसपा, द्रमुक वगैरह को केवल आदि में समेटकर आगे बढ़ना चाहता है तो उसकी मरज़ी है लेकिन वो स्थानीय आकांक्षाओं, स्थानीय मुद्दों, स्थानीय अभिव्यक्तियों की बारीक और अहम ज़रूरतों के प्रति उपेक्षा से भरा है। मैं नहीं मान सकता कि केंद्र चला रही पार्टियां ही प्रदेश चलाने की अकेली हकदार हैं। बहुदलीय प्रणाली में छोटे समूह अपनी विशिष्ट पहचान और मांगों के साथ सौदेबाजी की शक्ति रखते हैं। इसके विपरीत, दो दलीय तंत्र में छोटे समूहों को मजबूरन किसी एक बड़े 'अम्ब्रेला' के नीचे आना पड़ता है, जहाँ उनकी विशिष्ट आवाजें मेजोरिटेरियन नरेटिव में दब जाती हैं।

सच्चा लोकतांत्रिक वह है जो तीसरे, चौथे या पांचवें विकल्प के पनपने की जगह छोड़े। जो समर्थक यह कहते हैं कि "विकल्प क्या है?", वे दरअसल 'स्टॉकहोम सिंड्रोम' के शिकार हैं।उन्हें अपने ही राजनीतिक बंधकों से प्यार हो गया है। लोकतंत्र तब मरता है जब बहस 'मुद्दों' पर नहीं, बल्कि दो 'महारथियों' के अहंकार पर सिमट जाती है। लोकतंत्र केवल बहुमत का शासन नहीं, बल्कि विविध मतों की अभिव्यक्ति है। दो-दलीय प्रणाली जनता के सामने एक फाल्स डिलेमा उत्पन्न करती है। प्रसिद्ध राजनीतिक विश्लेषक मौरिस डुवर्गर ने डुवर्गर के नियम में स्पष्ट किया था कि फर्स्ट-पास्ट-द-पोस्ट प्रणाली अक्सर द्वि दलीय व्यवस्था को जन्म देती है, जो तीसरे विकल्प की संभावनाओं का गला घोंट देती है।जब दो पार्टियां सत्ता के केंद्र पर एकाधिकार कर लेती हैं, तो वे एक 'पॉलिटिकल डुपोली' की तरह व्यवहार करने लगती हैं। अर्थशास्त्री एंथोनी डाउन्स के 'मीडियन वोटर थ्योरम' के अनुसार, दोनों पार्टियां सत्ता पाने के लिए मध्यमार्गी मतदाताओं को लुभाने के चक्कर में इतनी समान हो जाती हैं कि उनके बीच का वैचारिक अंतर लगभग समाप्त हो जाता है।

जुबानी तीर

मैंने यह फैसला बहुत सोच-समझकर लिया है। जिस पार्टी को हमने ईमानदारी और पारदर्शिता के सिद्धांतों पर खड़ा किया था, वह आज भ्रष्ट और समझौता कर चुके लोगों के प्रभाव में आ गई है। ऐसे माहौल में काम करना मुश्किल हो गया था, इसलिए मैंने अलग रास्ता चुनना उचित समझा।

राघव चड्ढा (राजयसभा सांसद)

बीजेपी ने एक बार फिर पंजाब और देश की जनता के साथ धोखा किया है। लोकतंत्र को कमजोर करने के लिए लगातार चुने हुए प्रतिनिधियों को तोड़ने की कोशिश की जा रही है, लेकिन इससे आम आदमी पार्टी का संघर्ष और मजबूत होगा।

अरविन्द केजरीवाल (आप)

बड़े नेताओं पर दबाव बनाया जा सकता है, उन्हें डराया जा सकता है, लेकिन आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता न तो डरने वाले हैं और न ही झुकने वाले हैं। हमारी लड़ाई विचारों की है और वह जारी रहेगी।

सौरभ भरद्वाज (आप)

विज्ञापन एवं वार्षिक सब्सक्रिप्शन के लिए ऑफिस के पते पर सम्पर्क करें या फिर इन नम्बरों - 9667793987 या 9667793985 पर बात करें या इस पर media@bharatshri.com ईमेल करें।

पायरिया से निजात का आयुर्वेदिक मार्ग

दांत और मसूड़ों की सेहत का संपूर्ण समाधान

दांतों और मसूड़ों की बीमारी पायरिया आज के समय में एक आम लेकिन गंभीर समस्या बन चुकी है। अक्सर लोग इसे मामूली समझकर नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन यदि समय रहते इसका उपचार न किया जाए तो यह दांतों के कमजोर होने, हिलने और यहां तक कि गिरने का कारण भी बन सकता है। आयुर्वेद में पायरिया को केवल एक स्थानीय रोग नहीं, बल्कि शरीर के दोषों-विशेषकर कफ और पित्त के असंतुलन का परिणाम माना गया है। यही कारण है कि आयुर्वेदिक उपचार केवल लक्षणों को नहीं, बल्कि रोग के मूल कारण को ठीक करने पर केंद्रित होता है।

पायरिया क्या है और क्यों होता है?

पायरिया मूल रूप से मसूड़ों की बीमारी है, जिसमें मसूड़ों से खून आना, सूजन, दर्द, मुंह से दुर्गंध और दांतों में ढीलापन जैसे लक्षण दिखाई देते हैं। यह समस्या आमतौर पर दांतों की ठीक से सफाई न करने, ज्यादा मीठा खाने, तंबाकू या गुटखा सेवन, पाचन तंत्र की गड़बड़ी और शरीर में विषैले तत्वों के जमा होने से होती है।आयुर्वेद के अनुसार जब शरीर में "आम" यानी अपचित भोजन के अवशेष जमा हो जाते हैं, तो वे रक्त और ऊतकों को दूषित कर देते हैं। इसका प्रभाव मसूड़ों पर भी पड़ता है, जिससे पायरिया जैसी समस्या उत्पन्न होती है।

पायरिया के प्रमुख आयुर्वेदिक उपचार

बबूल का दातून

नीम और बबूल दोनों ही प्राकृतिक एंटीसेप्टिक माने जाते हैं। रोज सुबह नीम या बबूल की दातून करने से मसूड़े मजबूत होते हैं और बैक्टीरिया नष्ट होते हैं। यह प्राचीन पद्धति आज भी उतनी ही प्रभावी है जितनी पहले थी।

त्रिफला का उपयोग

त्रिफला (आंवला, हरड़, बहेड़ा) आयुर्वेद की एक शक्तिशाली औषधि है। रात में एक चम्मच त्रिफला चूर्ण गुनगुने पानी के साथ लेने से पाचन सुधरता है और शरीर के विषैले तत्व बाहर निकलते हैं। इसके अलावा त्रिफला के पानी से कुल्ला करने से मसूड़ों की सूजन कम होती है।

सरसों तेल और सेंधा नमक से मसाज

एक चुटकी सेंधा नमक को सरसों के तेल में मिलाकर मसूड़ों पर हल्के हाथ से मालिश करें। यह उपाय मसूड़ों को मजबूत बनाता है, खून आना बंद करता है और संक्रमण को कम करता है।

लौंग और इलायची

लौंग में प्राकृतिक दर्द निवारक और एंटीबैक्टीरियल गुण होते हैं। लौंग का तेल मसूड़ों पर लगाने या लौंग चबाने से दर्द और सूजन में राहत मिलती है। इलायची मुंह की दुर्गंध दूर करने में मदद करती है।

हल्दी और शहद का लेप

हल्दी एक शक्तिशाली एंटीसेप्टिक है। हल्दी और शहद को मिलाकर मसूड़ों पर लगाने से संक्रमण कम होता है और घाव जल्दी भरते हैं।

गिलोय और आंवला

गिलोय और आंवला शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाते हैं। इनका सेवन करने से शरीर अंदर से मजबूत होता है और पायरिया जैसी समस्याओं से लड़ने की शक्ति मिलती है।

जीवनशैली में बदलाव जरूरी

आयुर्वेद केवल दवाओं पर निर्भर नहीं करता, बल्कि जीवनशैली सुधार पर भी जोर देता है।

सही ब्रशिंग तकनीक

दिन में दो बार ब्रश करना और सही तकनीक अपनाना जरूरी है। बहुत जोर से ब्रश करने से मसूड़े कमजोर हो सकते हैं।

तंबाकू और गुटखा से दूरी

तंबाकू और गुटखा पायरिया के सबसे बड़े कारणों में से एक हैं। इनसे पूरी तरह दूरी बनाना ही सबसे अच्छा उपाय है।

संतुलित आहार

हरी सब्जियां, फल, विटामिन C से भरपूर खाद्य पदार्थ मसूड़ों को मजबूत बनाते हैं। ज्यादा मीठा और तला-भुना भोजन कम करना चाहिए।

पर्याप्त पानी पीना

पानी शरीर से विषैले तत्वों को बाहर निकालता है और मुंह को साफ रखने में मदद करता है।

योग और प्राणायाम का महत्व

योग और प्राणायाम भी पायरिया के उपचार में सहायक होते हैं।

अनुलोम-विलोम: शरीर में ऑक्सीजन का स्तर बढ़ाता है

कपालभाति: पाचन तंत्र को सुधारता है

भस्त्रिका प्राणायाम: रक्त संचार को बेहतर बनाता है

जब शरीर का रक्त संचार बेहतर होता है, तो मसूड़ों तक पोषण सही तरीके से पहुंचता है।

- घरेलू नुस्खे जो तुरंत राहत दें
- गुनगुने पानी में नमक डालकर कुल्ला करें
- नारियल तेल से ऑयल पुलिंग करें (10-15 मिनट)
- तुलसी के पत्तों का पाउडर दांतों पर लगाएं
- नींबू के छिलके से हल्की मालिश करें

ये सभी उपाय मुंह की सफाई और बैक्टीरिया को खत्म करने में मदद करते हैं।

कब डॉक्टर की जरूरत है

यदि पायरिया बहुत ज्यादा बढ़ चुका है, मसूड़ों से लगातार खून आ रहा है या दांत हिलने लगे हैं, तो केवल घरेलू उपाय पर्याप्त नहीं होते। ऐसे में आयुर्वेदिक चिकित्सक या दंत चिकित्सक से सलाह लेना जरूरी है।

पायरिया एक ऐसी समस्या है जिसे नजरअंदाज करना भारी पड़ सकता है। आयुर्वेद हमें सिखाता है कि हर रोग का इलाज हमारे आसपास मौजूद प्राकृतिक तत्वों में छिपा है। नीम, त्रिफला, हल्दी और अन्य आयुर्वेदिक उपाय न केवल पायरिया को ठीक करते हैं, बल्कि दांतों और मसूड़ों को लंबे समय तक स्वस्थ बनाए रखते हैं।जरूरत है केवल नियमितता, सही जीवनशैली और थोड़ी सी जागरूकता की। यदि हम समय रहते अपने दांतों और मसूड़ों की देखभाल शुरू कर दें, तो पायरिया जैसी समस्या से आसानी से बचा जा सकता है।

पाठकों के सवाल

क्या आपको स्वास्थ्य से जुड़ी कोई समस्या है और आप उसका समाधान आयुर्वेद के माध्यम से जानना चाहते हैं? अब आप अपने सवाल हमें भेज सकते हैं। आपके द्वारा भेजे गए चुनिंदा प्रश्नों का उत्तर अनुभवी आयुर्वेदाचार्य द्वारा दिया जाएगा और उन्हें इस पेज पर प्रकाशित किया जाएगा।

अपने सवाल हमें ईमेल करें
hi@bharatshri.com

कृपया अपने सवाल के साथ अपनी उम्र, शहर और समस्या का संक्षिप्त विवरण अवश्य लिखें, ताकि विशेषज्ञ सही सलाह दे सकें।

श्री महात्मा जीव गोस्वामी जी : कृष्ण प्रेम के अतल सागर और भक्ति के आचार्य

महात्मा जीव गोस्वामी जी अतल कृष्ण भक्ति सागर की गहराई और अचल चैतन्य शरणागति की स्थिरता के सुंदर समन्वय का प्रतीक थे। वे परम भगवत भक्त और रस सिद्ध विद्वान महात्मा थे। वल्लभ सम्प्रदाय में महामति प्रभु चरण हरिराय जी को जो स्थान मिला है वही स्थान गौड़ीय सम्प्रदाय में महात्मा जीव गोस्वामी जी को प्राप्त है। वे महात्मा सनातन और रूप गोस्वामी जी के सगे भतीजे थे। वे चैतन्य चरणारविंद के मधु के मुग्ध भ्रमर जैसे थे।

जिस समय अकबर सीकरी में ऐश्वर्य और लौकिक वैभव पर शासन कर रहे थे उसी समय श्री कृष्ण की लीला भूमि व्रज में महात्मा जीव गोस्वामी जी भगवद भक्ति और अलौकिक ऐश्वर्य से जीव मात्र को सचेत कर रहे थे।

पूर्वज और पवित्र जन्म

महात्मा जीव गोस्वामी जी के पूर्वज परम ऐश्वर्य सम्पन्न और भगवान में पूर्ण निष्ठा रखने वाले थे। वे दक्षिण के कर्णाट प्रांत के रहने वाले थे। वे भारद्वाज गोत्र के यजुर्वेदी ब्राह्मण थे। विक्रम सम्वत की सोलहवी शताब्दी में उनके पूर्वज पद्मनाभ नवहट्ट चले आए। हुसेन शाह के शासन काल में उनके पितामह कुमारदेव ने फतेहाबाद में रहना शुरू किया। कुमारदेव के तीन पुत्र थे - सनातन, रूप और अनुपम वल्लभ। सनातन और रूप मालाघर वसु के संपर्क से गौड़ के बादशाह हुसेन शाह की राजसभा में प्रधानमंत्री और निजी सचिव के पद पर क्रमशः प्रतिष्ठित हुए।

जीव गोस्वामी जी अनुपम वल्लभ के पुत्र थे। उनका जन्म पौष शुक्ल तृतीया को वाकला चन्द्र द्वीप में हुआ। यह जन्म विक्रम की सोलहवी शताब्दी के तीसरे चरण की समाप्ति पर और चौथे चरण के आरंभ में 1590 के पहले हुआ था। सनातन और रूप निस्संतान थे इसलिए वे जीव गोस्वामी जी को बहुत मानते थे। जीव गोस्वामी जी समस्त परिवार के प्रेम पात्र थे। उनकी शिक्षा दीक्षा की बहुत अच्छी व्यवस्था की गई थी।

चैतन्य महाप्रभु से दिव्य संबंध

ऐसा कहा जाता है कि सनातन और रूप को धन्य और कृतार्थ करने के लिए जब महाप्रभु चैतन्य देव का रामकेलि ग्राम में पदार्पण हुआ था तब बालक जीव गोस्वामी जी ने गंगा तटीय रमणीय उपवन के पीछे छिपकर महाप्रभु की दिव्य कान्ति से अपने नयन शीतल किए थे। मन ही मन उन्होंने अपने आप को उनके चरणों में प्रेम के माध्यम से समर्पित कर दिया था।

चैतन्य महाप्रभु के रामकेलि से चले जाने के बाद सनातन और रूप को राजकार्य से वैराग्य हो गया। रूप हुसेन शाह से छुट्टी लेकर चैतन्य देव से मिलने के लिए अपने छोटे भाई अनुपम के साथ वृन्दावन की ओर चल पड़े। रूप ने थोड़ा सा धन जीव गोस्वामी जी को देकर शेष ब्राह्मणों में बांट दिया। जीव गोस्वामी जी अधिकतर रूप के साथ नहीं बल्कि सनातन के ही पास रहते थे। पर वे भी बादशाह के कारागार में डाल दिए गए।

जीव गोस्वामी जी का मन लौकिक ऐश्वर्य भोग में बिल्कुल नहीं लगता था। उनके जीवन विकास पर सनातन

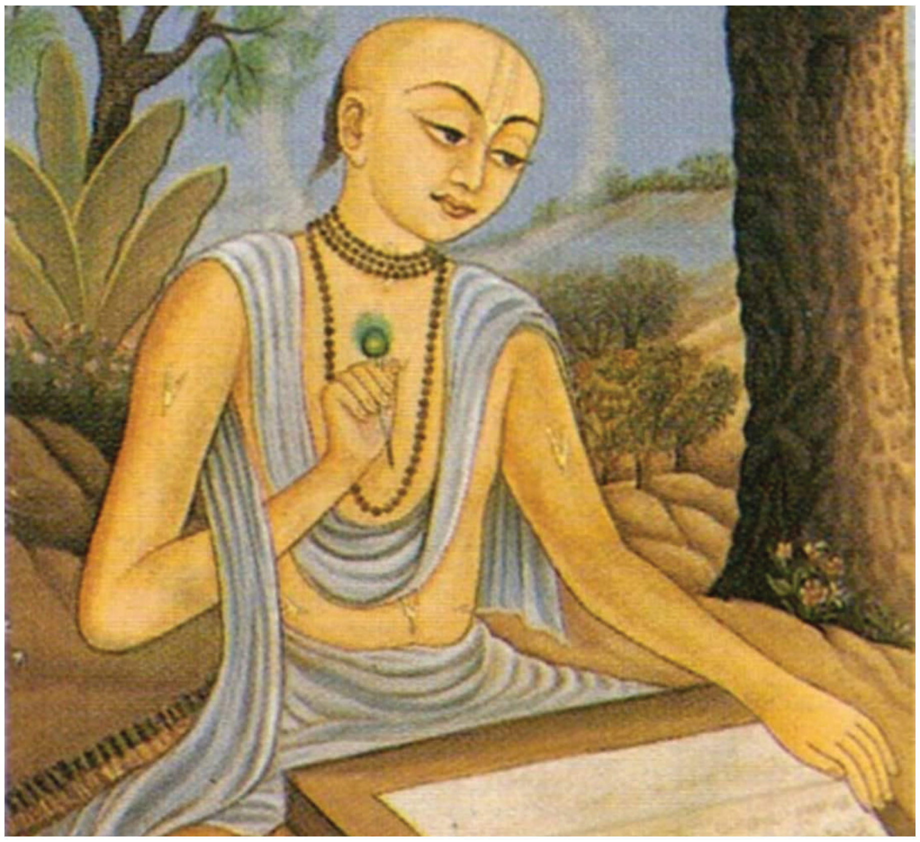

और रूप की भगवन्निष्ठा का बहुत बड़ा प्रभाव था। इधर सनातन भी कारागार से निकलकर प्रभु चैतन्य देव से मिलने काशी आ गए। रूप और अनुपम ने प्रयाग में चैतन्य से भेंट की। उनकी आज्ञा से दोनों भाई लुप्त तीर्थों के उद्धार और खोज के लिए वृन्दावन गए। कुछ दिनों के बाद चैतन्य देव के दर्शन के लिए रूप और अनुपम ने नीलाचल की यात्रा की पर मार्ग में ज्वर से अनुपम की मृत्यु हो गई।

जीवगोस्वामी जी की अवस्था उस समय लगभग बीस साल की थी। पिता की मृत्यु से उनके हृदय पर बड़ा आघात लगा। उनका मन वृन्दावन के लिए आकुल हो गया। उन्होंने सनातन और रूप के साथ वृन्दावन में रहकर श्री कृष्ण भक्ति में समय का सदुपयोग करने का निश्चय किया।

एक दिन रात को स्वप्न में उन्हें चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद का दर्शन हुआ। वे नित्यानंद के दर्शन के लिए नवद्वीप गए। घर बार और भोग ऐश्वर्य पर लात मारकर वे श्री कृष्ण के प्रेमी हो गए। उन्होंने आजीवन अखंड ब्रह्मचर्य का पालन किया। नित्यानंद ने उन्हें काशी जाकर विद्याध्ययन करने का आदेश दिया।

वृन्दावन में साधना और दीक्षा

जीव गोस्वामी जी काशी चले आए। उन्होंने भगवद भक्ति को जीवन का ध्येय स्थिर किया। काशी में उन्होंने सार्वभौम भट्टाचार्य के शिष्य मधुसूदन विद्यावाचस्पति से शास्त्रों का अध्ययन किया। वेदांत और न्याय आदि दर्शन शास्त्रों में वे पूर्ण निष्णात हो गए। काशी निवास काल में उन्होंने बड़े बड़े सिद्ध संतों और बीतरागी महात्माओं के दर्शन और सत्संग का रसास्वादन किया।

वे सनातन और रूप के पास वृन्दावन चले आए। रूप के साथ रहकर भक्ति शास्त्र का अध्ययन करने लगे। सनातन और रूप दोनों उन दिनों वृन्दावन में ही रहते थे। वृन्दावन की चिन्मय सौंदर्य माधुरी की उपासना और कृष्ण प्रेम प्राप्ति की दिव्य कामना में उनका मन रमने लगा। वे आजीवन वृन्दावन में ही रह गए। वृन्दावन उनका प्राण धन हो गया।

रूप गोस्वामी ने उन्हें विधि पूर्वक दीक्षा देकर अपने चरणों में आश्रय प्रदान किया। रूप ने दीक्षा देते समय कहा कि तुम वैराग्य का जीवन अपना रहे हो पर रेशमी परिधान शरीर पर सजाकर रखे हुए हो। मीराबाई ने गोस्वामी जी के पास प्रत्युत्तर भेजा कि मैं तो यह समझती थी कि वृन्दावन में पुरुष केवल श्री कृष्ण हैं पर आज यह पता चला कि कोई और भी है। मीरा ऐसी भक्त की वाणी तीर की तरह लग गई। जीव गोस्वामी आसन से उठ पड़े और मीरा को अपने दर्शन से धन्य ही नहीं किया बल्कि उनके दर्शन से स्वयं कृतार्थ हो गए। महात्मा जीव गोस्वामी वैराग्य रस रसिक संत थे।

भगवद भक्ति के गहरे विचार

महात्मा जीव गोस्वामी जी ने भगवद भक्ति के क्षेत्र में भजनानंद को स्वरूपानंद से अधिक श्रेयस्कर स्वीकार किया। भजनानंद से भगवान की भक्ति मिलती है जबकि स्वरूपानंद ब्रह्म ज्ञान प्रदान करता है। उन्होंने स्वीकार किया है कि भक्ति भगवान की ओर ले जाती है पर ज्ञान से ब्रह्मानुभूति की प्राप्ति होती है। भक्ति ज्ञान से श्रेष्ठ है ऐसी उनकी मान्यता थी।

उन्होंने श्रीमद भागवत पुराण को गौड़ीय वैष्णव चिंतन का प्रधान शास्त्र स्वीकार किया। चैतन्य देव के सिद्धांतों के अनुरूप रूप और सनातन गोस्वामी द्वारा प्रतिपादित भेदाभेद वाद के अचिन्त्य स्वरूप में उन्होंने गोप राज तनय नंदनंदन का दर्शन किया। भगवत सदर्भ में उनकी भगवत तत्त्व के संबंध में उक्ति है

'स्वरूपाद्यभिन्नत्वेन चिन्तयितुम् शक्यत्वाद् भेद भिन्नत्वेन चिन्त-यितुम् शक्यत्वाद् अभेदश्च प्रतीयते इति शक्तिशक्तिमतोर्भेदाभेदौ अङ्गीकृतौ । तौ च अचिन्त्यौ। स्वमते तु अचिन्त्यभेदाभेदावेव अचिन्त्य-शक्तित्वात् ।'

उन्होंने भक्ति को रस माना और इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि वैराग्य वह तत्व है जिसके द्वारा लौकिक वस्तुओं का भगवत सेवा में अनासक्ति पूर्वक उपयोग हो और श्री कृष्ण के प्रति प्रेम बढ़े। उन्होंने श्री कृष्ण को भगवत तत्त्व, राधा को महाभाव स्वरूपिणी और प्रेम को परतत्त्व महातत्त्व स्वीकार किया। जीव गोस्वामी उच्च कोटि के रसोपासक थे। उनकी रस उपासना का मूलभूत आधार श्री राधा कृष्ण विषयक परम प्रेम है।

अमर रचनाएँ

महात्मा जीव गोस्वामी जी ने 'गोपाल चम्पू', 'माधव महोत्सव' आदि ग्रंथों में श्री कृष्ण की विभिन्न वृन्दावन लीलाओं का पूर्ण रूप से वर्णन किया है। चैतन्य महाप्रभु की सतुष्टि के लिए सुख के लिए उन्होंने 'पूर्व गोपाल चम्पू' और 'उत्तर गोपाल चम्पू' की रचना में हाथ लगाया। दिव्य गति प्राप्ति और सुखमयता ही उनकी रचना की मूल भूमि है। 'उत्तर गोपाल चम्पू' में जीव गोस्वामी जी की स्वीकृति और स्पष्टीकरण है

'प्रागारब्धमभूत्तदेतदमल चम्पूद्वय यत्कृते तच्चेद हृदि शुद्धमाविरभवल्लोकद्वयस्यामृत, राधाकृष्णपरस्परव् यतिकरानन्दात्मना येन ते याता दिव्यर्गात वय सुखमय सर्वोर्द्धमध्यास्महे।'

उनकी प्रसिद्ध रचनाएँ हैं - माधव महोत्सव, गोपाल चम्पू, हरिनामामृत व्याकरण, षट् संदर्भ आदि। उन्होंने भक्ति सिद्धांत गोविंद विरुदावली और उपदेशामृत ग्रंथ भी लिखे।

अंतिम समय और अमर योगदान

अपने जीवन के अंतिम पैंसठ साल उन्होंने श्री कृष्ण के चरण चिंतन और भक्ति ग्रंथों के प्रणयन में वृन्दावन में बिताए। व्रज से कहीं भी बाहर न जाने का दृढ़ नियम था। वे निरंतर वृन्दावन में रहकर भगवान श्री कृष्ण के ऐश्वर्य, सौंदर्य और माधुर्य का रसास्वादन करते रहे।

सम्वत 1675 विक्रम के लगभग आश्विन शुक्ल तृतीया को वृन्दावन में ही उन्होंने नित्य धाम में प्रवेश किया। राधा दामोदर उनके परम उपास्य थे। उन्होंने आजीवन भगवद भक्ति के अमृत सागर में अवगाहन कर बड़े प्रेम से श्री राधा कृष्ण की लीला चिंतन का व्रत अनुष्ठान किया। अपनी सरस रचनाओं में सर्वत्र उन्होंने कृष्ण की लीला का अनुभव चित्रित किया है।

निस्संदेह जीव गोस्वामी सगुण संत साहित्य के विकास की एक बहुत बड़ी भागवती शक्ति थे। भक्तिशास्त्र के अपूर्व मर्मज्ञ थे। बड़े बड़े शास्त्र महारथी और ज्ञानी भक्ति के संबंध में उनकी सम्मति लिया करते थे। वे गौड़ीय वैष्णव विचारधारा के आचार्य थे। महात्मा जीव गोस्वामी जी का नाम भक्ति साहित्य के इतिहास में अमर है।

राष्ट्र को एक सूत्र में बांधते हैं हम
भारत श्री

अमेरिका और रूस के बीच भारत की असली भूमिका क्या?

राम माधव के बयान से उठे बड़े सवाल

राम माधव ने क्या कहा?

भाजपा के वरिष्ठ नेता और आरएसएस से जुड़े राम माधव ने 24 अप्रैल 2026 को अमेरिका के वाशिंगटन डीसी में हडसन इंस्टीट्यूट में एक चर्चा में बोलते हुए एक बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि भारत ने अमेरिका के कहने पर ईरान से तेल लेना बंद कर दिया, रूस से तेल लेना भी बंद कर दिया। विपक्ष की इतनी आलोचना के बावजूद हमने यह कदम उठाया। साथ ही अमेरिका ने हमारे निर्यात पर 50 प्रतिशत टैरिफ लगा दिया तो हमने ज्यादा कुछ नहीं कहा, चुपचाप सहन कर लिया। नई व्यापार डील में भी 18 प्रतिशत टैरिफ पर हम राजी हो गए। फिर राम माधव ने सवाल किया कि आखिर अमेरिका को और क्या चाहिए? हमने तो सब कुछ कर दिया। यह बयान भारत-अमेरिका रिश्तों की मजबूती दिखाने के लिए था लेकिन घर में तूफान खड़ा कर गया। राम माधव का मकसद था कि भारत ने अमेरिका के साथ कितना सहयोग किया है, इस पर सबको सोचना चाहिए। उन्होंने भारतीय विरोधी दलों की आलोचना का जिक्र भी किया कि घरेलू राजनीति में सरकार पर दबाव था फिर भी हमने राष्ट्रीय हित में फैसले लिए। इस बयान से लगता था कि भारत अमेरिका की हर मांग मान रहा है। लेकिन कुछ घंटों बाद ही राम माधव ने अपनी बात वापस ले ली। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा कि जो मैंने कहा वह गलत था। अब यह बयान पूरे देश में चर्चा का विषय बन गया है। लोग पूछ रहे हैं कि क्या भारत वाकई अमेरिका के दबाव में झुक रहा है या यह सिर्फ एक भाषण की गलती थी। इस घटना से साफ है कि विदेश नीति के मुद्दे कितनी आसानी से घरेलू राजनीति में घुल जाते हैं।

राजनीति में क्यों भड़की आग?

राम माधव के बयान के बाद विपक्षी पार्टियां खासकर कांग्रेस ने तुरंत हमला बोल दिया। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार अमेरिका के सामने घुटने टेक रही है। कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाया कि राष्ट्रीय हितों से समझौता हो रहा है। वे बोले कि देश के हित में तेल खरीदना बंद करना या टैरिफ सहन करना भारत की स्वतंत्र नीति नहीं दिखाता। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो गया और लोग बहस करने लगे। कई विपक्षी नेता कह रहे थे कि राम माधव ने खुद कबूल कर लिया कि सरकार अमेरिका के इशारे पर चल रही है। इस बयान से राजनीतिक माहौल

गरम हो गया। कुछ लोगों ने इसे भाजपा की विदेश नीति की कमजोरी बताया तो कुछ ने कहा कि यह अमेरिका में भारतीय डायस्पोरा को संतुष्ट करने की कोशिश थी। लेकिन सरकार के समर्थक बोले कि राम माधव ने सिर्फ सहयोग की बात कही थी, इसमें गलत कुछ नहीं। फिर भी विवाद बढ़ता गया क्योंकि तेल और व्यापार जैसे मुद्दे आम लोगों के जीवन से जुड़े हैं। पेट्रोल-डीजल की कीमतें, महंगाई सब पर असर पड़ता है। राम माधव के बयान ने विपक्ष को नया हथियार दे दिया। उन्होंने पूछा कि अगर सरकार ने इतना किया तो अमेरिका फिर भी क्यों नाराज है। इस बहस में मीडिया ने भी खूब कवरेज दिया। टीवी डिबेट में लोग दोनों तरफ की बातें सुन रहे थे। कुछ विशेषज्ञ कह रहे थे कि यह बयान भारत की रणनीतिक स्वायत्तता पर सवाल उठाता है। कुल मिलाकर राजनीति में यह मुद्दा कई दिनों तक छाया रहा। लोग समझ रहे थे कि विदेश नीति सिर्फ कागजों पर नहीं बल्कि घरेलू राजनीति से भी जुड़ी होती है। राम माधव का बयान भले ही छोटा था लेकिन उसने बड़े सवाल खड़े कर दिए।

बयानों की कितनी सच्चाई है?

अब सवाल यह है कि राम माधव के बयान में कितनी सच्चाई थी। सबसे पहले ईरान से तेल की बात। 2019 में अमेरिका ने ईरान पर प्रतिबंध लगाए तो भारत ने तेल खरीदना लगभग बंद कर दिया था। उस समय भी सरकार ने अमेरिका के साथ तालमेल रखा। लेकिन रूस से तेल की बात पूरी तरह गलत निकली। भारत ने रूस से तेल खरीदना कभी बंद नहीं किया। उल्टा यूक्रेन युद्ध के बाद भारत ने रूस से सस्ता तेल ज्यादा खरीदा। 2026 में भी मार्च में रूस से आयात रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया। रूस अब भारत का सबसे बड़ा तेल आपूर्तिकर्ता है। ईरान से हाल में कुछ आयात फिर शुरू हुआ लेकिन वह भी अमेरिका की छूट के साथ। 50 प्रतिशत टैरिफ की बात पर भी स्पष्टता है। अमेरिका ने भारत के निर्यात पर टैरिफ लगाए थे लेकिन भारत ने इसका जोरदार विरोध किया। सरकार ने चुपचाप नहीं सहा बल्कि बातचीत की। बाद में नई व्यापार डील में टैरिफ 18 प्रतिशत पर आ गया। राम माधव ने खुद माना कि उनका बयान तथ्यों से गलत था। उन्होंने कहा कि भारत ने रूस से तेल रोकने पर कभी सहमति नहीं दी और टैरिफ का विरोध किया। यह बयान अमेरिका में एक पैनल चर्चा में दूसरे वक्ता को जवाब देने के लिए दिया गया था। विशेषज्ञ कहते हैं कि ईरान वाला हिस्सा पुराना सच है लेकिन रूस वाला बिल्कुल नहीं। टैरिफ में भी भारत ने अपने हित की रक्षा की। कुल मिलाकर बयान में तथ्य गलत थे लेकिन मकसद भारत-अमेरिका दोस्ती दिखाना था। लोग अब समझ रहे हैं कि विदेश नीति में छोटी गलती भी बड़ी बहस पैदा कर सकती है। सरकार ने हमेशा कहा है कि हम अपनी ऊर्जा जरूरतों के हिसाब से फैसले लेते हैं। सच्चाई यह है कि भारत दोनों तरफ संतुलन बनाए रखता है।

नेता ने ऐसा क्यों बोला?

राम माधव एक अनुभवी नेता हैं। वे विदेश नीति पर खुलकर बोलते हैं। उन्होंने अमेरिका में क्यों ऐसा कहा? शायद उनका मकसद भारत की कोशिशों को सामने लाना था। वे बता रहे थे कि भारत अमेरिका के साथ अच्छे रिश्ते रखने के लिए कितना कर रहा है। विपक्ष की आलोचना का जिक्र करके उन्होंने दिखाया कि घरेलू दबाव के बावजूद सरकार आगे बढ़ रही है। अमेरिका में भारतीय समुदाय में भी भारत-अमेरिका रिश्तों पर चिंता थी। ट्रंप प्रशासन के समय कुछ तनाव की खबरें आई थीं। शायद राम माधव उस तनाव को कम करने की कोशिश कर रहे थे। उन्होंने कहा कि हमने इतना किया फिर भी अमेरिका को और क्या चाहिए। यह एक तरह का सवाल था कि रिश्ते में आपसी सम्मान हो। लेकिन भाषण में तथ्य गलत हो गए। बाद में उन्होंने माफी मांग ली और कहा कि वे दूसरे वक्ता को जवाब दे रहे थे। कुछ लोग मानते हैं कि यह एक अनजाने में हुई गलती थी। राम माधव आरएसएस के अंतरराष्ट्रीय मामलों के जानकार माने जाते हैं। उनका बयान शायद भारत की रणनीतिक स्वायत्तता और अमेरिका के साथ साझेदारी के बीच संतुलन दिखाने का प्रयास था। लेकिन विपक्ष ने इसे सरकार की कमजोरी बता दिया। कुल मिलाकर यह बयान दिखाता है कि नेता कभी-कभी उत्साह में बोल जाते हैं। महत्वपूर्ण यह है कि सरकार ने तुरंत स्पष्टीकरण देकर स्थिति संभाली। इससे पता चलता है कि भारत अपनी नीति पर अडिग है। राम माधव का उद्देश्य अच्छा था लेकिन तरीका गलत पड़ा।

भारत-अमेरिका रिश्तों पर क्या असर?

इस पूरे विवाद का भारत-अमेरिका रिश्तों पर क्या असर पड़ेगा? दोनों देश रणनीतिक साझेदार हैं। व्यापार, सुरक्षा, ऊर्जा सब क्षेत्रों में सहयोग बढ़ रहा है। राम माधव का बयान भले ही विवादास्पद रहा लेकिन इससे रिश्ते खराब नहीं होंगे। बल्कि दोनों तरफ से बातचीत बढ़ेगी। भारत हमेशा कहता है कि वह अपनी जरूरतों के हिसाब से तेल खरीदता है। अमेरिका भी समझता है कि भारत जैसे बड़े देश को ऊर्जा सुरक्षा चाहिए। टैरिफ मुद्दा भी व्यापार डील से सुलझ रहा है। विशेषज्ञ कहते हैं कि ऐसे बयान छोटे होते हैं लेकिन वे सोचने पर मजबूर करते हैं। भारत को अपनी स्वतंत्र नीति बनाए रखनी चाहिए। साथ ही अमेरिका के साथ मजबूत दोस्ती भी जरूरी है। यह घटना याद दिलाती है कि विदेश नीति में हर शब्द का ध्यान रखना पड़ता है। राजनीति गरम हुई लेकिन अब सब सामान्य हो रहा है। लोग उम्मीद करते हैं कि दोनों देश आपसी सम्मान से आगे बढ़ेंगे। राम माधव का बयान एक सबक बन गया है। भारत दुनिया का बड़ा देश है। वह न किसी के दबाव में झुकता है न अपनी जरूरतें भूलता है। भविष्य में ऐसे मुद्दे और अच्छे तरीके से सुलझाए जाएंगे। कुल मिलाकर यह विवाद रिश्तों को मजबूत बनाने का मौका भी दे सकता है।

गुरुकृपा, आत्मबोध और प्रेम से परमात्मा प्राप्ति का सच्चा मार्ग

@ भारतश्री ब्यूरो

यदि आप इतिहास देखेंगे तो पाएंगे कि 14-15वीं शताब्दी में राजा रामचन्द्र ने अपने पुत्र ब्रह्मदेव राय के नाम से इस शहर का नाम रायपुर रखा था और गुरुदेव जी ने अपने पुत्र के नाम से इसका नामकरण मनदीप पुर किया है। यह हम सबके लिए सौभाग्य की बात है। कहावत है कि इतिहास अपने आपको दोहराता है। रायपुर स्टील उद्योग के लिए बहुत प्रसिद्ध है। लोहे के उद्योग के राजा व देवता भगवान शनिदेव होते हैं। जब शनि हमारे जीवन में आता है तो कष्टों को खत्म करने के लिए आता है। ऐसे ही जब हमारे जीवन में गुरु आते हैं और हमें पाठ देते हैं, उससे जितने भी दुख, कष्ट हैं उनका निवारण हो जाता है और हम अपने आपको मजबूत कर पाते हैं। जब हम पाठ करते हैं तो हमें कष्टों से लड़ने की शक्ति प्राप्त होती है। हमारे जीवन में राम कृष्ण और शनिदेव साक्षात गुरुदेव जी ही हैं। रायपुर में आते ही गुरुदेव जी ने कहा कि यहां पर संगत के बहुत ही कष्ट और दुख हैं। वे जब होटल में पहुंचे तो आराम नहीं किया और न ही भोजन किया, वे कष्ट निवारण हेतु पाठ में लग गए और हमसे कहा कि समागम में जाओ और संगत से पाठ करवाओ। गुरुदेव ने हमें मां ललिता, त्रिपुर सुन्दरी का पाठ दिया। जब हम सभी हजारों की संख्या में जाप करेंगे तो उस जाप का फल सभी को मिलेगा।

कल जब हम गुरुदेव के पास बैठे थे तो उन्होंने एक कथा सुनाई कि एक राजा रोज दान किया करता था और उसके दरवाजे से कोई खाली हाथ नहीं जाता था। एक दिन एक भिखारी हाथ में डोलू (पात्र) लेकर आया और कहने लगा कि इसमें जितना सोना आ जाए उतना मुझे दान दे दो। राजा ने उस पात्र में सोमा डाला तो वह गायब हो गया। इतना ही नहीं कि उसका सारा खजाना खाली हो गया लेकिन उसका पात्र नहीं भरा। राजा ने कहा कि तुम कोई साधारण भिखारी नहीं हो तो वह जोर-जोर से हंसने लगा। उसने कहा कि मैं श्मशान के पास से गुजर रहा था तो यह खोपड़ी मिल गई जिसे मैंने भिक्षा पात्र बना लिया और इसी पात्र में भिक्षा ग्रहण करता हूं। मुझे यह अनुभव हुआ है कि मनुष्य की खोपड़ी कभी भरतो ही नहीं है, हमारे मन में हमेशा लालसा बनी रहती है। जब हम स्कूल में पढ़ते हैं तो सोचते हैं कालेज में जाएं। कालेज के बाद सोचते हैं कि जाँब लग जाए इसके बाद शादी हो जाए। जब बच्चे हो जाते हैं तो जिंदगी के 20-25 साल और उनके पालन में बीत जाते हैं फिर सोचते हैं कि बच्चों की शादी हो जाए और पोता-पोती हो जाएं। इस प्रकार हमारी इच्छाएं कभी समाप्त नहीं होती। इसलिए हमें ऐसे कर्मदेवता की आवश्यकता होती है जो हमारे कष्टों को काट दें। जब कोई मूवी देखकर आते हैं तो दो तीन घंटे के लिए खुशी महसूस करते हैं लेकिन घर आकर फिर वही स्थिति हो जाती है। क्योंकि अस्थायी खुशी थी। हम इस जीवन में इनके लिए नहीं परमात्मा के नाम के लिए आए हैं। जब तक हम दुर्गा मां के मंत्रों का पाठ नहीं कर पाते तब तक हमारा जीवन और हमारी खोपड़ी खालो रहती हैं, पाठ से ही यह भरती है और सुख समृद्धि आती है।

वासना से परे, आत्मा से परमात्मा तक की यात्रा

प्रेम किसी स्त्री-पुरुष के संबंध का रूप नहीं है, यह वासना नहीं है। प्रेम की बहुत गहन परिभाषा है। जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभु पाये, प्रेम गली अति सांकरी जा मे दो न समाये। भगवान श्रीकृष्ण की सोलह हजार रानियां थीं और वे सभी से समान रूप से प्रेम किया करते थे लेकिन वह वासना का स्वरूप नहीं था। हमें पति-पत्नी के रूप में काम को धारण तो करना पड़ता है लेकिन इसका मूल प्रेम होता है। जिस घर में स्त्री की इज्जत नहीं होती वह घर नर्क के समान होता है। राधा ने जो भगवान श्रीकृष्ण से किया वह प्रेम था, वासना नहीं थी। प्रेम भाई-भाई में, बहन-भाई में, माता-पिता और पुत्र में, मित्र का मित्र में हो सकता है।

आत्मा से परमात्मा तक सत्य की खोज

हर मनुष्य को आत्मा और परमात्मा के विषय में जानना बहुत आवश्यक है। भगवान श्रीकृष्ण ने गीता में कहा है कि मेरी दो प्रकार की प्रकृति है-परा और अपरा हैं। पृथ्वी, आकाश, वायु, जल, अग्नि, मन, बुद्धि और अहंकार ये अपरा हैं और जो परा है वह आत्मा है। परा प्रकृति अपरा का दोहन करके जीवन को संचालित करती है। अर्थात अपरा से बना शरीर ही आत्मा का वास होता है। यही तत्व परमात्मा का है। अपरा प्रकृति नष्ट हो जाती है लेकिन परा सत्य, सनातन और शाश्वत है। आत्मा के विषय में भगवान कृष्ण ने कहा है कि ये न तो शस्त्र से कटती है, न अग्नि में जलती है, न पानी में गलती है, न वायु इसे सुखा सकती है। यह अभेद्य है तथा स्थिर है। सबका आत्मा एक है। न यह कहीं आती है न जाती है। लोग कहते हैं कि आत्मा ऊपर चली गई, या किसी लोक में चली गई लेकिन ऐसा नहीं होता है। आत्मा सर्वव्यापी है। दुर्गा सप्तशती में वर्णन है कि मैं ऊपर-नीचे, अगल-बगल सब जगह हूं। हमें मनुष्य शरीर इसलिए मिला है कि यह जानें हम इस पृथ्वी पर क्यों आए हैं? हम इस संसार में आकर माया में लिप्त हो जाते हैं और अपने उद्देश्य से भटक जाते हैं। किसी तत्ववेत्ता सद्गुरु की शरण में जाकर विनम्र निवेदन करने पर ही यह तत्वज्ञान प्राप्त होता है।

कलयुग में परमात्मा प्राप्ति का सहज रहस्य

केवल मनुष्य ही नहीं देवी-देवताओं ने भी लंबे समय तक तपस्या की है। मां पार्वती ने कई वर्षों तक तपस्या की और भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त किया। इसी प्रकार भगवान शिव ने हजारों वर्षों तक तप करके मां दुर्गा से मंत्र प्राप्त किया। हमारे पुराणों और ग्रंथों में ऐसे अनेकों उदाहरण हैं कि जब ऋषियों, साधुओं ने लंबे समय तक तप करके सिद्धियां प्राप्त की हैं। इतना ही नहीं असुरों ने भी कठिन तप करके वरदान प्राप्त किए हैं। इनकी बात करें तो मां पार्वती आदि परा शक्ति थीं लेकिन भगवान ने कलयुग में इतना सरल मार्ग प्रदान किया है। अगर तुम दिन में थोड़ी देर भी मेरा नाम ले लोगो तब भी मैं तुम्हें प्राप्त हो जाऊंगा जबकि सतयुग में पूरा जीवन तप करने के बावजूद भी परमात्मा के दर्शन नहीं होते थे।

भीषण गर्मी की चपेट में देश

कई शहरों में पारा 46 डिग्री के पार, राहत के नाम पर छिटपुट बारिश

@ सौम्या चौबे

देश के बड़े हिस्से इस समय प्रचंड गर्मी की मार झेल रहे हैं। उत्तर, पश्चिम और मध्य भारत के कई राज्यों में तापमान लगातार नए रिकॉर्ड के करीब पहुंच रहा है। रविवार को राजस्थान, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र के कम से कम सात शहरों में तापमान 46 डिग्री सेल्सियस से ऊपर दर्ज किया गया, जिससे जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ। सबसे अधिक तापमान महाराष्ट्र के अकोला में 46.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो देश में सबसे ज्यादा रहा। इसके अलावा अमरावती में 46.8C, बांदा में 46.6C, वर्धा और बाड़मेर में 46.4C, जबकि जैसलमेर और यवतमाल में 46C तापमान दर्ज किया गया। इन इलाकों में लू की स्थिति बेहद गंभीर बनी हुई है।

उत्तर प्रदेश में लू का प्रकोप, 60 जिलों में अलर्ट

उत्तर प्रदेश में गर्मी ने विकराल रूप ले लिया है। मौसम विभाग ने राज्य के 60 जिलों में लू चलने की चेतावनी जारी की है। बांदा प्रदेश का सबसे गर्म शहर रहा, जहां तापमान 46.6C तक पहुंच गया। इसके साथ ही 14 जिलों में आंधी और बारिश का अलर्ट भी जारी किया गया है, जिससे कुछ राहत की उम्मीद जताई जा रही है।

मध्य प्रदेश में पहली बार 45C पार

मध्य प्रदेश में भी तापमान तेजी से बढ़ रहा है। पर्यटन स्थल खजुराहो में पहली बार तापमान 45C दर्ज किया गया। वहीं इंदौर और भोपाल में पारा 43C के आसपास बना हुआ है, जबकि जबलपुर में 43.5C तापमान दर्ज किया गया। साथ ही इंदौर और उज्जैन में 'वार्म नाइट' की चेतावनी दी गई है, जिसका मतलब है कि रात के समय भी तापमान सामान्य से अधिक बना रहेगा।

राजस्थान में तपिश के बीच बारिश की हल्की राहत

राजस्थान में दिनभर भीषण गर्मी के बाद शाम को मौसम ने करवट ली। बीकानेर, अजमेर, भीलवाड़ा और चित्तौड़गढ़ सहित कई इलाकों में बादल छाए और कुछ स्थानों पर हल्की बारिश हुई। इससे लोगों को अस्थायी राहत जरूर मिली, लेकिन तापमान में खास गिरावट नहीं आई।

बिहार में गर्मी के साथ हादसे

बिहार में भी गर्मी का असर तेज बना हुआ है। राज्य के आठ जिलों में तापमान 40C के पार पहुंच गया। रोहतास में सबसे ज्यादा 43.2C तापमान दर्ज किया गया।गर्मी के कारण दो लोगों की मौत की खबर है, जबकि नेपाल सीमा से सटे जिलों में आंधी और बिजली गिरने की घटनाओं में पांच लोगों की जान चली गई। सुपौल, रक्सौल और मधुबनी समेत कई जिलों में तेज बारिश और आंधी देखने को मिली।दरभंगा में दिन के समय ही काले बादल छा

गए, जिससे अंधेरा जैसा माहौल बन गया। वहीं किशनगंज और कटिहार में तेज आंधी-बारिश से पेड़ उखड़ गए और आम की फसल को नुकसान पहुंचा।

उत्तराखंड में स्कूल बंद

गर्मी का असर पहाड़ी राज्यों में भी देखने को मिल रहा है। देहरादून में तापमान बढ़ने के चलते प्रशासन ने 12वीं तक के स्कूलों को अस्थायी रूप से बंद कर दिया है। यह फैसला छात्रों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए लिया गया है।मध्य प्रदेश के महू, भोपाल, सीहोर और रतलाम सहित कई इलाकों में रविवार शाम को बारिश हुई। महू में तेज बारिश दर्ज की गई, जबकि भोपाल में हल्की बूंदाबांदी हुई। इन बारिशों से तापमान में मामूली गिरावट आई और लोगों को थोड़ी राहत मिली, लेकिन मौसम विभाग का कहना है कि यह राहत अस्थायी है और अगले कुछ दिनों तक गर्मी का प्रकोप जारी रह सकता है।

स्वास्थ्य पर बढ़ता खतरा

डॉक्टरों के अनुसार, इस तरह की भीषण गर्मी में हीट स्ट्रोक, डिहाइड्रेशन और अन्य स्वास्थ्य समस्याओं का खतरा बढ़ जाता है। विशेष रूप से बच्चों, बुजुर्गों और पहले से बीमार लोगों को अधिक सावधानी बरतने की जरूरत है। लोगों को सलाह दी जा रही है कि वे दोपहर के समय घर से बाहर निकलने से बचें, पर्याप्त पानी पिएं और हल्के कपड़े पहनें। तेज गर्मी और आंधी-बारिश के मिले-जुले प्रभाव से कृषि क्षेत्र भी प्रभावित हो रहा है। बिहार और उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में आम और अन्य फसलों को नुकसान पहुंचा है। इसके अलावा, शहरों में बिजली की मांग बढ़ गई है, जिससे कई जगहों पर बिजली कटौती की समस्या भी सामने आ रही है।

आगे क्या कहता है मौसम विभाग

मौसम विभाग के अनुसार, आने वाले कुछ दिनों तक उत्तर और मध्य भारत के कई हिस्सों में लू की स्थिति बनी रह सकती है। हालांकि, कुछ क्षेत्रों में आंधी और हल्की बारिश की संभावना भी जताई गई है, जिससे आंशिक राहत मिल सकती है। देश इस समय भीषण गर्मी और बदलते मौसम के दोहरे प्रभाव से जूझ रहा है। जहां एक ओर तापमान नए रिकॉर्ड बना रहा है, वहीं दूसरी ओर अचानक आने वाली आंधी और बारिश नई चुनौतियां खड़ी कर रही हैं।ऐसे में प्रशासन और आम लोगों दोनों के लिए सतर्क रहना जरूरी है।

अप्रैल में जून जैसी तपिश, उत्तर प्रदेश में हीटवेव का कहर, पारा 47C के पार

उत्तर प्रदेश इन दिनों भीषण गर्मी की चपेट में है, जहां अप्रैल महीने में ही जून जैसी झुलसा देने वाली गर्मी महसूस की जा रही है। प्रदेश के कई हिस्सों में तापमान 47 डिग्री सेल्सियस के करीब या उससे ऊपर पहुंच गया है। तेज धूप, गर्म हवाओं और उमस भरे मौसम ने जनजीवन को बुरी तरह प्रभावित किया है। सोमवार सुबह से ही आसमान में हल्के बादलों की आवाजाही के बीच तेज धूप और लू का असर साफ दिखाई दिया।

बांदा बना सबसे गर्म, लगातार दूसरे दिन रिकॉर्ड

बांदा प्रदेश का सबसे गर्म शहर बना हुआ है। रविवार को यहां अधिकतम तापमान 46.6C दर्ज किया गया, जबकि एक दिन पहले यह 47.4C तक पहुंच गया था, जो देश में सबसे अधिक था। मौसम विभाग के अनुसार, आने वाले दिनों में भी तापमान में बहुत ज्यादा गिरावट की संभावना नहीं है, हालांकि बीच-बीच में हल्की बारिश राहत दे सकती है।

अस्पतालों में बढ़े हीट स्ट्रोक और डिहाइड्रेशन के मरीज

भीषण गर्मी का असर स्वास्थ्य सेवाओं पर भी साफ दिखाई दे रहा है। वाराणसी (काशी) के सरकारी अस्पतालों में उल्टी-दस्त और हीट स्ट्रोक के मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ी है। मरीजों के बढ़ते दबाव को देखते हुए अस्पताल प्रशासन ने विशेष इंतजाम किए हैं।यहां एक अलग कोल्ड रूम बनाया गया है, जहां गंभीर मरीजों को ठंडे वातावरण में रखा जा सके। हीट स्ट्रोक के मरीजों के लिए चार विशेष बेड लगाए गए हैं और वार्ड में बाथ टब की व्यवस्था भी की गई है, ताकि शरीर का तापमान तेजी से कम किया जा सके।

आग और तकनीकी खराबी की घटनाएं बढ़ीं

गर्मी के कारण आग लगने और तकनीकी खराबी की घटनाएं भी बढ़ गई हैं। गोरखपुर में एक घर में लगे विंडो एसी में अचानक आग लग गई, जो देखते ही देखते पूरे घर में फैल गई। हालांकि, परिवार के लोगों ने समय रहते बाहर निकलकर अपनी जान बचा ली।इसी तरह कानपुर में गर्मी के चलते ट्रांसफॉर्मर में आग लग गई, जिससे पास की दो दुकानें जलकर राख हो गईं। वहीं अमेठी में ट्रांसफॉर्मर को ठंडा रखने के लिए उस पर पाइप से लगातार पानी डाला जा रहा है, ताकि ओवरहीटिंग से बचाया जा सके।

ट्रेन यात्रा भी बनी चुनौती

भीषण गर्मी का असर रेल सेवाओं पर भी देखने को मिला। आगरा में कामाख्या एक्सप्रेस के थर्ड एसी कोच में एयर कंडीशनिंग सिस्टम खराब हो गया, जिससे यात्रियों

को लगभग 6 घंटे तक गर्मी में सफर करना पड़ा। यात्रियों के विरोध के बाद कानपुर में कोच बदला गया।

मेरठ में सन्नाटा, लोग घरों में कैद

मेरठ में तापमान 42C के आसपास पहुंच गया है। तेज धूप और उमस के कारण लोग घरों से बाहर निकलने से बच रहे हैं। सड़कों पर दिन के समय सन्नाटा पसरा हुआ है।स्वास्थ्य विभाग और प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि वे पर्याप्त मात्रा में पानी पिएं, खुद को हाइड्रेटेड रखें और दोपहर 12 बजे से 3 बजे के बीच घर से बाहर निकलने से बचें।भारतीय मौसम विभाग ने प्रदेश के 60 जिलों में लू का अलर्ट जारी किया है, जबकि 14 जिलों में आंधी और बारिश की संभावना जताई गई है। हालांकि, विशेषज्ञों का कहना है कि यह राहत अस्थायी हो सकती है और गर्मी का असर पूरी तरह खत्म नहीं होगा।

आम लोगों की परेशानी

भीषण गर्मी से आम जनजीवन अस्त-व्यस्त हो गया है। प्रयागराज आए एक युवक ने बताया कि यहां की गर्मी दिल्ली से भी ज्यादा महसूस हो रही है। "गर्म हवाएं इतनी तेज हैं कि बाहर निकलना मुश्किल हो गया है। खुद को ठंडा रखने के लिए जलजीरा और ठंडे पेय का सहारा लेना पड़ रहा है,डॉक्टरों के अनुसार, इस तरह की गर्मी में हीट स्ट्रोक का खतरा काफी बढ़ जाता है। लोगों को सलाह दी गई है कि वे हल्के कपड़े पहनें, सिर को ढककर रखें और ज्यादा समय तक धूप में रहने से बचें।बच्चों, बुजुर्गों और पहले से बीमार लोगों को विशेष सावधानी बरतने की जरूरत है। यदि किसी को चक्कर आना, तेज सिरदर्द या उल्टी जैसे लक्षण महसूस हों, तो तुरंत चिकित्सकीय सहायता लेनी चाहिए।

बिजली और पानी की मांग में बढ़ोतरी

गर्मी के कारण बिजली और पानी की मांग में भी भारी बढ़ोतरी हुई है। कई शहरों में बिजली कटौती की शिकायतें सामने आ रही हैं। ट्रांसफॉर्मर पर बढ़ते लोड के कारण खराबी और आग लगने की घटनाएं बढ़ रही हैं।उत्तर प्रदेश इस समय भीषण गर्मी और लू के दोहरे संकट से जूझ रहा है।

राष्ट्र को एक सूत्र में बांधते हैं हम
भारत श्री

सीजीमाली पहाड़ पर संघर्ष

खनन, कानून और आदिवासी अधिकारों के बीच उलझी एक कहानी

रायगढ़ा के सीजीमाली पहाड़ में बॉक्साइट खनन को लेकर विवाद गहराया, 8 ग्रामसभाओं की सहमति पर सवाल, 230.15 करोड़ के राजनीतिक चंदे की चर्चा, 3 किमी जंगल क्षेत्र में निर्माण, विरोध में 21 लोग हिरासत में; मामला हाईकोर्ट की निगरानी में

@ मनीष पांडेय

ओडिशा के दक्षिणी हिस्से में स्थित रायगढ़ा जिले की पहाड़ियों में बसा सीजीमाली क्षेत्र लंबे समय से अपनी प्राकृतिक सुंदरता, जैव विविधता और आदिवासी संस्कृति के लिए जाना जाता रहा है। घने जंगलों, पहाड़ी ढलानों और वन्यजीवों से भरपूर इस इलाके को स्थानीय लोग "छिपा हुआ स्वर्ग" मानते हैं। लेकिन हाल के वर्षों में यह क्षेत्र विकास बनाम पर्यावरण और अधिकारों की बहस का केंद्र बन गया है। सीजीमाली पहाड़ केवल अपनी खूबसूरती के लिए ही नहीं, बल्कि इसके नीचे मौजूद बॉक्साइट जैसे खनिज संसाधनों के कारण भी चर्चा में है।

बॉक्साइट एल्युमिनियम उत्पादन का प्रमुख कच्चा माल है और देश की कई बड़ी कंपनियां इस संसाधन पर नजर रखती रही हैं। इसी क्रम में वेदांता लिमिटेड ने भी इस क्षेत्र में खनन की संभावना तलाशने में रुचि दिखाई।हालांकि, यह इलाका वन कानूनों के दायरे में आता है। ऐसे में किसी भी खनन परियोजना के लिए स्थानीय ग्राम सभाओं की सहमति अनिवार्य होती है। यह प्रावधान वनाधिकार और पर्यावरण संरक्षण के संतुलन को बनाए रखने के लिए बनाया गया है।

फर्जी ग्रामसभा बनाने की क्या जरुरत पड़ी?

स्थानीय स्तर पर सबसे बड़ा विवाद ग्राम सभाओं की सहमति को लेकर सामने आया। आरोप है कि जिन आठ गांवों की सहमति आवश्यक थी, वहां प्रक्रिया को लेकर पारदर्शिता पर सवाल उठे। कुछ ग्रामीणों का कहना है कि जिस दिन अनुमोदन की प्रक्रिया हुई, उस दिन बाहरी लोगों की मौजूदगी और प्रशासनिक स्तर पर जल्दबाजी देखी गई।आरोप यह भी लगाए गए कि एक ही समय में कई गांवों से सहमति दिखाने का दावा किया गया, जिससे प्रक्रिया की विश्वसनीयता पर प्रश्नचिह्न लगा। बाद में स्थानीय ग्रामीणों ने बैठक कर इस कथित सहमति को अस्वीकार करने की बात कही।

मामला अदालत तक पहुंचा,फिर समाधान क्यों नहीं?

विवाद बढ़ने के बाद यह मामला अदालत तक पहुंचा। ओडिशा हाईकोर्ट ने मामले की जांच के आदेश दिए। अदालत ने यह सुनिश्चित करने पर जोर दिया कि किसी भी परियोजना में कानूनी प्रक्रियाओं और स्थानीय अधिकारों का सम्मान किया जाए।हालांकि, इस बीच प्रशासनिक स्तर पर कुछ अनुमतियों को लेकर भी चर्चा होती रही। पर्यावरणीय मंजूरी और वन क्षेत्र में गतिविधियों को लेकर विभिन्न स्तरों पर निर्णय लिए गए, जिन पर अलग-अलग पक्षों की राय सामने आई।

राजनीतिक चंदा और आरोप

इस पूरे प्रकरण में राजनीतिक फंडिंग को लेकर भी आरोप-प्रत्यारोप सामने आए। रिपोर्ट्स के अनुसार, वेदांता लिमिटेड ने विभिन्न राजनीतिक दलों को इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से चंदा दिया था। इसमें भारतीय जनता पार्टी को लगभग 230.15 करोड़ रुपये, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को 125 करोड़ रुपये और बीजू जनता दल को करीब 40 करोड़ रुपये दिए जाने की बात कही जाती है।हालांकि, इन चंदों और परियोजना अनुमोदन के बीच किसी प्रत्यक्ष संबंध को लेकर आधिकारिक तौर पर कोई निष्कर्ष सामने नहीं आया है। विशेषज्ञों का मानना है कि इस तरह के मामलों में पारदर्शिता और स्वतंत्र जांच बेहद जरूरी होती है।

आखिर कब तक होती रहेगी जंगल की कटाई?

मार्च 2026 के आसपास क्षेत्र में निर्माण कार्य शुरू होने की खबरें सामने आईं। बताया गया कि लगभग 3 किलोमीटर के जंगल क्षेत्र में गतिविधियां शुरू की गईं। इससे पर्यावरणविदों और स्थानीय समुदायों में चिंता बढ़ गई।वन क्षेत्र में किसी भी प्रकार की कटाई या निर्माण कार्य के लिए सख्त नियम होते हैं। ऐसे में यह सवाल उठाया गया कि क्या सभी आवश्यक मंजूरियां पूरी तरह से प्राप्त की गई थीं या नहीं।स्थानीय स्तर पर कुछ समूहों ने इन गतिविधियों का विरोध किया। उनका कहना था कि यह परियोजना न केवल पर्यावरण के लिए हानिकारक है, बल्कि उनके पारंपरिक जीवन और आजीविका को भी प्रभावित करेगी।विरोध प्रदर्शनों के दौरान पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच टकराव की घटनाएं भी सामने आईं। कुछ रिपोर्ट्स में यह उल्लेख किया गया कि पुलिस ने कार्रवाई करते हुए कुछ लोगों को हिरासत में लिया। इनमें महिलाओं के शामिल होने की भी बात कही गई।हालांकि, प्रशासन का पक्ष यह रहा कि कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए आवश्यक कदम उठाए गए। किसी भी कार्रवाई को कानूनी प्रक्रिया के तहत ही किया गया।

आदिवासियों के साथ इतना अत्याचार क्यों?

सीजीमाली क्षेत्र में रहने वाले अधिकांश लोग आदिवासी समुदाय से आते हैं, जिनकी आजीविका जंगल और प्राकृतिक संसाधनों पर निर्भर करती है। ऐसे में किसी भी परियोजना का सीधा असर उनके जीवन पर पड़ता है।विशेषज्ञों का कहना है कि इस तरह के क्षेत्रों में विकास परियोजनाओं को लागू करते समय स्थानीय समुदायों की सहमति, उनकी संस्कृति और अधिकारों का विशेष ध्यान रखा जाना चाहिए।

वनाधिकार कानून इसी उद्देश्य से बनाया गया था, ताकि विकास और संरक्षण के बीच संतुलन बना रहे।सीजीमाली जैसे क्षेत्र जैव विविधता के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण माने जाते हैं। यहां बाघ, हाथी और कई दुर्लभ प्रजातियों का निवास है। ऐसे में खनन गतिविधियों से इन पारिस्थितिक तंत्रों पर प्रभाव पड़ने की आशंका जताई जाती है।पर्यावरणविदों का मानना है कि बड़े पैमाने पर खनन से जल स्रोतों, वन्यजीवों और स्थानीय जलवायु पर नकारात्मक असर पड़ सकता है।

विवाद का समाधान क्या है?

यह पूरा मामला केवल एक क्षेत्र तक सीमित नहीं है, बल्कि यह देशभर में चल रही उस बहस को दर्शाता है, जिसमें विकास परियोजनाओं और पर्यावरण संरक्षण के बीच संतुलन खोजने की कोशिश की जा रही है।एक ओर औद्योगिक विकास और संसाधनों के उपयोग की आवश्यकता है, तो दूसरी ओर पर्यावरण और स्थानीय समुदायों के अधिकारों की रक्षा भी उतनी ही महत्वपूर्ण है।सीजीमाली पहाड़ का मुद्दा कई स्तरों पर जटिल है-पर्यावरण, कानून, राजनीति और समाज सभी इससे जुड़े हैं। जहां एक ओर विकास की जरूरत है, वहीं दूसरी ओर यह सुनिश्चित करना भी जरूरी है कि यह विकास न्यायसंगत और टिकाऊ हो।

आने वाले समय में अदालतों, सरकार और समाज की भूमिका इस दिशा में अहम होगी कि ऐसे मामलों में संतुलन कैसे बनाया जाए। पारदर्शिता, संवाद और कानून का पालन ही इस तरह के विवादों का स्थायी समाधान बन सकता है।

अनुराग ठाकुर की मछली भात: भाजपा का मांसाहार पर क्या रुख है?

बंगाल चुनाव में अनुराग का वीडियो वायरल

पश्चिम बंगाल में अभी विधानसभा चुनाव चल रहे हैं और इस बीच भाजपा सांसद अनुराग ठाकुर का एक वीडियो सोशल मीडिया पर काफी चर्चा में है। अप्रैल 2026 के पहले हफ्ते में कोलकाता में प्रचार के दौरान अनुराग ठाकुर और अन्य भाजपा नेता मछली और चावल यानी माछ भात खाते दिखे। उनके माथे पर चंदन का तिलक था और गले में भगवा गमछा बंधा हुआ था। उन्होंने रिपोर्टरों से कहा कि हम मांस मछली और चावल खा रहे हैं। यह वीडियो इसलिए वायरल हुआ क्योंकि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने दावा किया था कि भाजपा सत्ता में आई तो राज्य में मछली अंडे और मांस खाने पर रोक लगा देगी। अनुराग ठाकुर ने इस दावे को गलत बताया और कहा कि भाजपा 16 राज्यों में और एनडीए 20 राज्यों में सरकार चला रही है जहां किसी की भाषा खान-पान या पूजा पर कोई पाबंदी नहीं है। बंगाल की संस्कृति में मछली का खाना बहुत आम है। लोग इसे रोजाना खाते हैं और इससे जुड़े कारोबार भी चलते हैं। भाजपा इस वीडियो के जरिए यह संदेश देना चाहती है कि उनकी पार्टी बंगाल की परंपराओं का सम्मान करती है। विपक्षी पार्टियां जैसे तृणमूल कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने इसे चुनावी चाल बताया। उन्होंने कहा कि भाजपा उत्तर भारत में सनातन संस्कृति की बात करती है लेकिन यहां वोट के लिए मछली खा रही है। इस घटना ने लोगों के बीच बहस शुरू कर दी है कि क्या भाजपा का रुख क्षेत्र के हिसाब से बदलता है। कई लोग इसे सकारात्मक मान रहे हैं कि पार्टी स्थानीय संस्कृति को अपनाती है। लेकिन कुछ का कहना है कि यह सिर्फ वोट हासिल करने की रणनीति है। कुल मिलाकर यह वीडियो भाजपा की छवि को नरम करने में मदद कर रहा है लेकिन साथ ही सवाल भी उठा रहा है।

हेमंता शर्मा का साफ संदेश

असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा जिन्हें लोग हेमंता शर्मा के नाम से भी जानते हैं उन्होंने भी बंगाल चुनाव में भाजपा के पक्ष में प्रचार करते हुए मांसाहार पर बड़ा बयान दिया। उन्होंने ममता बनर्जी को चुनौती देते हुए कहा कि मैं दीदी से दो किलो ज्यादा मांस खा जाऊंगा। उनका कहना था कि भाजपा शासित राज्यों में मछली और मांस खाने पर कोई रोक नहीं है। लोग जितना चाहें खा सकते हैं। सिर्फ गौ मांस यानी बीफ के बारे में उन्होंने कहा कि असम में कानून के मुताबिक सार्वजनिक जगहों पर इसे नहीं खाया जा सकता लेकिन घर में खाने की छूट है। उन्होंने बंगाल के लोगों को आश्वासन दिया कि भाजपा सत्ता में आने पर मछली मांस या अंडे बंद नहीं करेगी। हेमंता शर्मा ने कहा कि असम में भाजपा सरकार है फिर भी लोग खुलकर मछली और मांस खाते हैं। सिर्फ गाय की रक्षा के लिए कुछ नियम हैं जो देश के कई हिस्सों में पहले से हैं। उनका यह बयान इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि असम भी पूर्वोत्तर का राज्य है जहां मांसाहार की परंपरा मजबूत है। विपक्ष ने इसे भाजपा की दोहरी नीति बताया। कुछ नेताओं का कहना है कि उत्तर भारत में भाजपा सख्ती करती है लेकिन पूर्वोत्तर में लचीला रवैया अपनाती है। हेमंता शर्मा के बयान ने भाजपा को बंगाल में स्थानीय लोगों के करीब लाने में मदद की। लोग अब सोच रहे हैं कि पार्टी का स्टैंड कितना एक जैसा है। यह बात भी सामने आई कि भाजपा विभिन्न राज्यों की संस्कृति को ध्यान में रखकर काम करती है। इससे पार्टी की रणनीति साफ होती है कि वह वोट बैंक के हिसाब से अपनी छवि बनाती है। कुल मिलाकर यह बयान भाजपा को मांसाहार विरोधी की छवि से दूर ले जाने वाला साबित हुआ।

उत्तर प्रदेश और बिहार में अलग तस्वीर

दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश और बिहार जैसे राज्यों में भाजपा की तस्वीर कुछ अलग दिखती है। यहां भाजपा अक्सर विपक्षी नेताओं को मांसाहार करने पर टारगेट करती है। उदाहरण के लिए जब तेजस्वी यादव ने नवरात्रि के दौरान मछली खाने की तस्वीर पोस्ट की तो भाजपा नेताओं ने इसे सनातन संस्कृति का अपमान बताया। इसी तरह बिहार में लालू प्रसाद यादव जैसे नेताओं के मटन खाने पर भी सवाल उठाए जाते हैं। उत्तर प्रदेश में कांवर यात्रा के समय मांस की दुकानों पर रोक लगाई जाती है। कुछ जगहों पर मांस की बिक्री सार्वजनिक जगहों पर बंद रखी जाती है। भाजपा का कहना है कि यह हिंदू भावनाओं का सम्मान है और गौ रक्षा के लिए जरूरी है। बिहार में भी हाल ही में मांस की खुली बिक्री पर बहस हुई थी। विपक्ष कहता है कि भाजपा सनातन की छवि बनाकर विपक्ष को बदनाम करती है। लेकिन जब बंगाल या असम जैसे राज्यों में अपनी जरूरत पड़ती है तो मांस खाने का समर्थन करती है। लोग पूछते हैं कि क्या भाजपा का नियम राज्य के हिसाब से अलग अलग है। उत्तर भारत में जहां हिंदू बहुसंख्यक हैं वहां सख्ती दिखाई जाती है जबकि पूर्वोत्तर या बंगाल में लचीलापन। यह बात राजनीतिक विश्लेषकों को भी सोचने पर मजबूर करती है। भाजपा का तर्क है कि हर राज्य की अपनी परंपरा है और पार्टी उसी के अनुसार काम करती है। लेकिन आलोचक कहते हैं कि इससे पार्टी की विचारधारा में असंगति दिखती है। इस तरह उत्तर और पूर्व के बीच का अंतर भाजपा के स्टैंड को सवालों के घेरे में खड़ा करता है।

सनातन छवि और क्षेत्रीय अनुकूलन

भाजपा खुद को सनातन संस्कृति का रक्षक बताती है। सनातन में अक्सर शाकाहार को बढ़ावा दिया जाता है और गौ माता की पूजा की जाती है। पार्टी के कई नेता उत्तर भारत में शाकाहार की बात करते हैं और विपक्ष को मांसाहारी कहकर हमला बोलते हैं। लेकिन बंगाल और असम जैसे राज्यों में अनुराग ठाकुर और हेमंता शर्मा जैसे नेता मांसाहार का समर्थन करते नजर आते हैं। यह क्षेत्रीय अनुकूलन कहलाता है। भाजपा का मानना है कि भारत विविधता वाला देश है। हर जगह की खान-पान की आदत अलग है। इसलिए एक साइज सबके लिए फिट नहीं हो सकती।

विपक्षी पार्टियां इसे दोहरापन बताती हैं। उनका कहना है कि सनातन की छवि सिर्फ वोट के लिए इस्तेमाल होती है। जब जरूरत पड़ती है तो भाजपा खुद मछली या मांस खाकर लोकल कल्चर अपनाती है। कई सामान्य लोग इस पर सोचते हैं कि राजनीति में सिद्धांत कितने मजबूत हैं। कुछ का मानना है कि यह व्यावहारिक राजनीति है। पार्टी को वोट जीतने के लिए स्थानीय लोगों की भावनाओं का ध्यान रखना पड़ता है। लेकिन कुछ लोग निराशा जताते हैं कि इससे सनातन मूल्यों की सच्चाई प्रभावित होती है। भाजपा के समर्थक कहते हैं कि मांस खाना व्यक्तिगत पसंद है। पार्टी किसी को जबरदस्ती नहीं रोकती। सिर्फ गौ हत्या पर कानून है जो पूरे देश में लागू है। इस तरह सनातन छवि और वास्तविकता के बीच संतुलन बनाना भाजपा के लिए चुनौती बना हुआ है।

भाजपा स्टैंड की समीक्षा

अब सवाल यह है कि भाजपा का मांसाहार पर स्टैंड आखिर क्या है। एक तरफ अनुराग ठाकुर बंगाल में मछली खाकर और हेमंता शर्मा मांस का चैलेंज देकर कहते हैं कि कोई रोक नहीं है। दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश और बिहार में विपक्ष को मांस खाने पर घेरा जाता है। यह स्थिति राजनीति की जटिलता दिखाती है। भाजपा का तर्क है कि वह क्षेत्रीय जरूरतों के हिसाब से काम करती है। कोई राष्ट्रीय स्तर पर मांसाहार बंद करने का कानून नहीं लाया गया है। सिर्फ गौ रक्षा और सार्वजनिक व्यवस्था के लिए नियम हैं। विपक्ष इसे दोहरी नीति कहता है और कहता है कि भाजपा सनातन का नाम लेकर वोट बटोरती है लेकिन जरूरत पड़ने पर लचीला रवैया अपनाती है। सामान्य जनता के बीच इस बहस ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। लोग सोच रहे हैं कि राजनीतिक दल अपनी छवि के लिए कितना कुछ बदल सकते हैं। कुछ इसे अच्छा मानते हैं क्योंकि इससे विविधता का सम्मान होता है। कुछ का कहना है कि इससे सिद्धांत कमजोर होते हैं। कुल मिलाकर भाजपा का यह स्टैंड दिखाता है कि भारतीय राजनीति में खान-पान जैसे मुद्दे भी वोट बैंक के लिए इस्तेमाल होते हैं। भविष्य में देखना होगा कि पार्टी इस रुख को कितना एकसमान रख पाती है। फिलहाल यह घटनाक्रम सोचने का मौका देता है कि सनातन संस्कृति और आधुनिक राजनीति का मेल कैसे हो सकता है।

तुम्हारा प्रेम

तुम्हारा प्रेम शॉल की तरह है
निहायत नर्म और मुलायम

सहूलत और सलाहियत से भरा
हर मौसम में अनुकूल

पर यह ऊन का नहीं
विश्वास और अनुभूतियों के तंतुओं से

जीवन के करघे पर बुना
लाल रंग में रँगा

मेरी धमनियों और शिराओं में बहता हुआ
इसे ओढ़ते ही मौसम सुहाना हो जाता है

ओढ़ने से केवल ठंडक ही नहीं मिटती
जन्मों-जन्मों की प्यास भी मिटती है

समय से परे है यह शॉल
न यह पुराना पड़ता

न इसका क्षय होता
पीड़ा और अकेलेपन को हर लेता है

शरीर को ही नहीं
आत्मा को भी ढक लेता है

छाया की तरह है
कभी दृश्य

कभी अदृश्य
पर हर क्षण विद्यमान और अनुभूत

मैं ढूँढ़ ही लूँगी तुम्हें

सुनो! अंतहीन नहीं है
पपीहे की प्रतीक्षा

अखंड विश्वास है उसे
चौमासा आएगा

स्वाति की बूँदें बरसाएगा
मैं भी भरोसा कर सकती हूँ क्या...?

कर सकती हूँ क्योंकि यही मेरे वश में है
लेकिन तुम्हारा कोई ठिकाना नहीं

कहाँ खोजूँ तुम्हे...
भीड़ के मेले में या यहीं-कहीं आस-पास

या कि दूर किसी देश में करते हो वास
मेरे चारों ओर होती है तुम्हारी आहट

गूँजती है तुम्हारी खिलखिलाहट
तुम नहीं मिलते

तुम-सा भी कोई नहीं मिलता
तुम्हारा व्यक्तित्व मेल नहीं खाता किसी से

तुम्हारी सहजता बुलाती है मुझे
मैं ढूँढ़ ही लूँगी तुम्हें एक न एक दिन

सुनो! तुम बिल्कुल न बदलना
हो सके तो प्यार से

ऐसे ही लबालब भरे रहना।

एक दिन

आए बाए कान कटाए
लोखरी का गमन कराए... झुर्र

और हम दोनों हो जाते फुर्र
अब सोचती हूँ तो बचपन का यह खेल

जीवन के खेल का रिहर्सल लगता है
एक-एक कर सब फुर्र्रर्र होते चले गए

फुर्र्रर्र होना और एक दिन
फ़ना हो जाना ही नियति है

जितनी गहरी होती जाती है यह प्रतीति
उतनी ही शिद्दत से याद आता है यह खेल

भाई के साथ दोनों हाथों से
पकड़कर एक-दूसरे के कान

बारी-बारी से बार-बार
अपनी-अपनी ओर खींचते हुए

सस्वर गाते थे यह सधा हुआ गान
आए बाए कान कटाए

लोखरी का गमन कराए
फिर एकाएक बोलकर 'झुर्र'

हो जाते थे फुर्र
अक्सर दुखती रहती थीं

देर तक कानों की बालियाँ
ऊपर से बरसती थीं माँ की गालियाँ

लेकिन रुका नहीं कभी खेल
लड़ते-झगड़ते हुए भी

न मन ही कभी हुआ बेमेल
खेल-खेल में हम तुम बड़े हो गए

ज़िंदगी की रेस में खड़े हो गए
भोली-सी सुबह की छँटती गई लाली

सुख-दुख के किनारों बीच
सरकती रही जीवन की गाड़ी

दुनियादारी में पड़े तो समझ आया
कच्चे और पक्के रिश्तों का फ़र्क

और हाँ! कान भी तो होते हैं
कच्चे और पक्के

होते हैं कान के जो कच्चे
उनके रिश्ते

कभी नहीं होते हैं पक्के।

विभूति तिवारी
नई पीढ़ी की कवि-गीतकार।

विवाद के बाद धीरेंद्र शास्त्री ने मांगी माफी

शिवाजी महाराज पर बयान से सियासत तेज, स्पष्टीकरण में भावना का हवाला

@ शोभित यादव

शिवाजी महाराज पर बयान के बाद बढ़ा विवाद, माफी के बावजूद सियासी और सामाजिक प्रतिक्रिया तेज

बयान पर विवाद बढ़ा, शास्त्री ने मांगी माफी
शिवाजी महाराज पर टिप्पणी से सियासत गरमाई
संदर्भ तोड़ा गया कहकर दिया स्पष्टीकरण
विपक्ष ने बताया इतिहास से छेड़छाड़
चार बच्चों वाले बयान पर भी सफाई

बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री द्वारा दिए गए एक बयान को लेकर उपजा विवाद अब नया मोड़ ले चुका है। छत्रपति शिवाजी महाराज और उनके गुरु समर्थ रामदास स्वामी के संबंध में की गई टिप्पणी पर तीखी प्रतिक्रिया के बाद शास्त्री ने सार्वजनिक रूप से माफी मांग ली है। हालांकि, उनके स्पष्टीकरण के बावजूद राजनीतिक और सामाजिक हलकों में बहस थमती नजर नहीं आ रही।

प्रेस कॉन्फ्रेंस में सफाई और माफी

रविवार को नागपुर में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में धीरेंद्र शास्त्री ने कहा कि उनके बयान को संदर्भ से काटकर प्रस्तुत किया गया। उन्होंने स्पष्ट किया कि उनका उद्देश्य किसी भी तरह से शिवाजी महाराज का अपमान करना नहीं था, बल्कि उनकी महानता और संतों के प्रति समर्पण को रेखांकित करना था।उन्होंने कहा, मैं जिस स्वराज और हिंदू राष्ट्र की भावना का सम्मान करता हूं, उसमें छत्रपति शिवाजी महाराज का स्थान सर्वोच्च है। उनके बारे में नकारात्मक बोलना तो दूर, मैं ऐसा सोच भी नहीं सकता। अगर मेरे शब्दों से किसी की भावनाएं आहत हुई हैं, तो मैं इसके लिए क्षमा प्रार्थी हूं।

विवाद की जड़ क्या थी?

दरअसल, नागपुर में एक कार्यक्रम के दौरान शास्त्री ने एक प्रसंग का उल्लेख करते हुए कहा था कि शिवाजी महाराज युद्धों से थक चुके थे और उन्होंने अपनी जिम्मेदारियां त्यागने की इच्छा जताई थी। उन्होंने यह भी कहा कि महाराज अपना मुकुट लेकर गुरु समर्थ रामदास के पास पहुंचे थे और उसे उनके चरणों में रख दिया था।शास्त्री के अनुसार, तब रामदास स्वामी ने उन्हें कर्तव्य का बोध कराते हुए मुकुट वापस उनके सिर पर रखा और कहा कि कठिन परिस्थितियों में भी अपने दायित्वों का निर्वहन करना ही सच्ची सेवा है।हालांकि, इतिहासकारों और कई राजनीतिक नेताओं ने इस कथन को ऐतिहासिक तथ्यों के विपरीत बताते हुए कड़ी आपत्ति जताई।

संदर्भ अलग था, धीरेन्द्र शास्त्री का तर्क

शास्त्री ने अपने बचाव में कहा कि वह केवल एक शिष्य और गुरु के बीच की भक्ति और समर्पण का उदाहरण दे रहे थे। उन्होंने महाभारत का हवाला देते हुए कहा कि जैसे अर्जुन युद्ध से विचलित हुए थे और तब भगवान कृष्ण ने उन्हें गीता का उपदेश दिया था, उसी प्रकार यह प्रसंग भी कर्तव्य और समर्पण को समझाने के लिए था।उन्होंने कहा, हम संतों के प्रति महाराज की भक्ति को दर्शा रहे थे, लेकिन एक छोटा सा हिस्सा निकालकर उसे अलग अर्थ में प्रस्तुत कर दिया गया।

राजनीतिक प्रतिक्रियाएं तेज

इस बयान के बाद महाराष्ट्र की राजनीति में तीखी प्रतिक्रियाएं सामने आईं। पूर्व राज्यसभा सदस्य संभाजीराजे छत्रपति ने शास्त्री के ज्ञान पर सवाल उठाते हुए कहा कि उन्हें इतिहास की सही समझ नहीं है। उन्होंने यह भी कहा कि मध्यप्रदेश के महान योद्धा छत्रसाल बुंदेला ने शिवाजी महाराज से प्रेरणा लेकर मुगलों के खिलाफ संघर्ष किया था।संभाजीराजे ने शास्त्री को "इतिहास से अनभिज्ञ" बताते हुए उनके कार्यक्रमों पर रोक लगाने की मांग की।

कांग्रेस और अन्य दलों का विरोध

महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाल ने इस बयान को इतिहास को तोड़-मरोड़कर पेश करने की कोशिश बताया। उन्होंने केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और राज्य के उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से भी इस मुद्दे पर स्पष्ट रुख अपनाने की मांग की।फडणवीस ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि इतिहास की पुस्तकों में ऐसा कोई उल्लेख नहीं मिलता और सभी को जिम्मेदारी के साथ बयान देना चाहिए।कांग्रेस नेता विजय वडेट्टीवार ने इसे "इतिहास का विकृत रूप" करार दिया।

शिवसेना और एनसीपी का हमला

शिवसेना (उद्धव गुट) के प्रवक्ता संजय राउत ने भी शास्त्री के बयान की कड़ी आलोचना की। उन्होंने कहा, छत्रपति शिवाजी महाराज एक संप्रभु शासक थे। यह कहना कि उन्होंने अपना राज्य किसी और को सौंप दिया था, एक ऐतिहासिक पाप है।वहीं, एनसीपी (शरद पवार गुट) के विधायक रोहित पवार ने महाराष्ट्र में शास्त्री के प्रवेश पर प्रतिबंध लगाने की मांग की। उन्होंने आरोप लगाया कि इस तरह के बयानों को मंच देने में सत्ता पक्ष की भी भूमिका है।

चार बच्चों वाले बयान पर भी सफाई

इसी कार्यक्रम में दिए गए एक अन्य बयान को लेकर भी शास्त्री विवादों में घिर गए थे, जिसमें उन्होंने लोगों से चार बच्चे पैदा करने और उनमें से एक को आरएसएस को समर्पित करने की बात कही थी।इस पर सफाई देते हुए शास्त्री ने कहा कि उनका आशय किसी संगठन को बच्चा देने से नहीं, बल्कि बच्चों को राष्ट्रवादी और संस्कारी बनाने से था। उन्होंने कहा, चाहे वह कलेक्टर बने, शिक्षक बने या किसी अन्य क्षेत्र में जाए, उसका दृष्टिकोण राष्ट्रहित में होना चाहिए।

सामाजिक और वैचारिक बहस

इस पूरे घटनाक्रम ने एक बार फिर धार्मिक प्रवचनों और ऐतिहासिक तथ्यों के बीच संतुलन की आवश्यकता पर बहस छेड़ दी है। विशेषज्ञों का मानना है कि सार्वजनिक मंचों पर दिए गए बयानों में ऐतिहासिक सटीकता और संवेदनशीलता दोनों का ध्यान रखना जरूरी है, खासकर जब बात ऐसे महान व्यक्तित्वों की हो, जिनका समाज पर गहरा प्रभाव रहा है।

धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री की माफी के बावजूद यह विवाद पूरी तरह शांत होता नहीं दिख रहा। जहां एक ओर उनके समर्थक इसे गलतफहमी बता रहे हैं, वहीं विरोधी इसे इतिहास के साथ छेड़छाड़ करार दे रहे हैं।

4 बच्चे पैदा करो, एक संघ को दे दो: बागेश्वर बाबा का बयान क्यों छेड़ रहा है बहस?

नागपुर का कार्यक्रम और बाबा का सीधा आह्वान

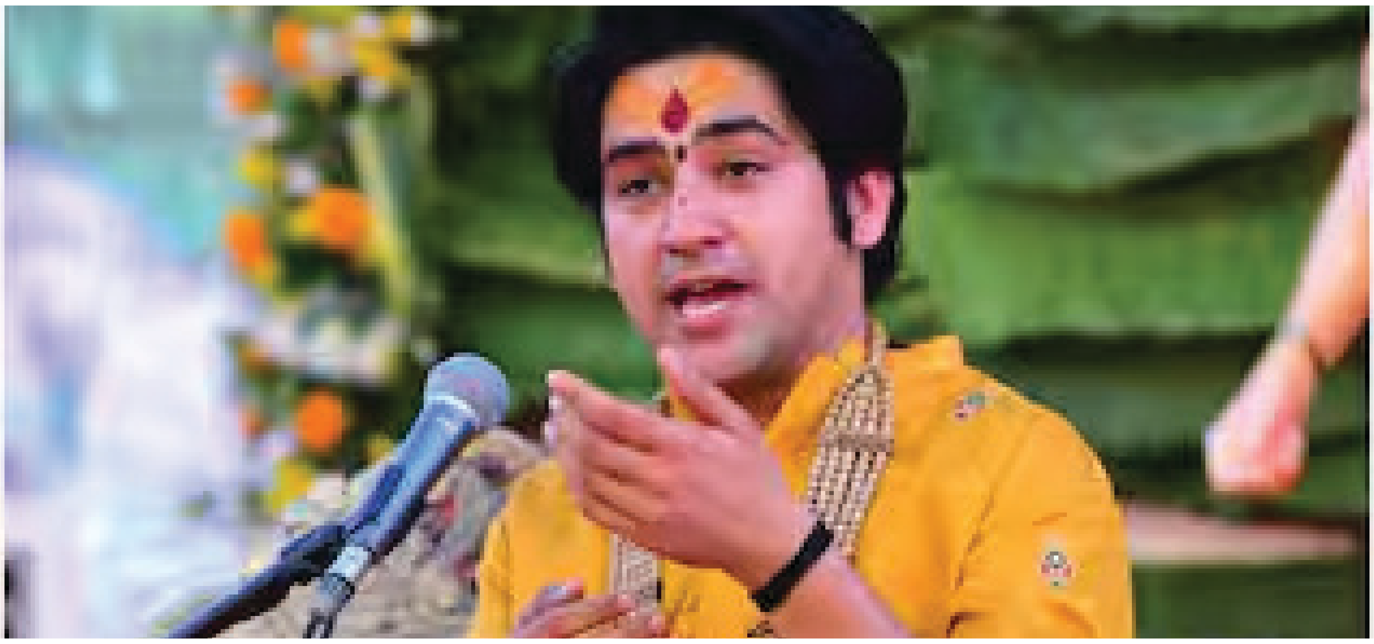

पिछले कुछ दिनों में पूरे देश में एक बयान की काफी चर्चा चल रही है। यह बयान बागेश्वर धाम के धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री यानी बाबा बागेश्वर का है। 24 अप्रैल 2026 को महाराष्ट्र के नागपुर में भारत दुर्गा मंदिर के शिलान्यास कार्यक्रम में उन्होंने यह बात कही। वहां राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक मोहन भागवत, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी जैसे बड़े लोग मौजूद थे। कई संत महात्मा और आम लोग भी बड़ी संख्या में आए थे। बाबा ने साफ कहा, बच्चे चार पैदा करो लेकिन एक स्वयंसेवक संघ को दे दो। उन्होंने आरएसएस की तारीफ करते हुए बताया कि जब आपदा आती है तो लोग अपनी जान बचाने के लिए भागते हैं लेकिन संघ के कार्यकर्ता दूसरों की मदद करने के लिए दौड़ पड़ते हैं।

बाबा ने कहा कि इस तरह का बच्चा राष्ट्र सेवा और सनातन धर्म की रक्षा में काम आएगा। कार्यक्रम का मुख्य काम मंदिर की नींव रखना था जो हिंदू संस्कृति को मजबूत करने का प्रतीक माना जा रहा है। इस बयान के बाद सोशल मीडिया पर लोग अपनी राय दे रहे हैं। कुछ कह रहे हैं कि यह सकारात्मक सोच है जो समाज सेवा को बढ़ावा देगी। वहीं कुछ लोग इसे परिवार की जिम्मेदारी पर बोझ बता रहे हैं। बाबा पहले भी चार बच्चों की बात कर चुके हैं लेकिन इस बार संघ को एक बच्चा समर्पित करने का आह्वान नया और चर्चित हो गया। यह कार्यक्रम नागपुर जैसे आरएसएस के गढ़ में हुआ जिससे यह और ज्यादा ध्यान खींच रहा है। लोग सोच रहे हैं कि क्या यह सिर्फ धार्मिक अपील है या इससे बड़े बदलाव की शुरुआत हो सकती है। कुल मिलाकर यह बयान आम परिवारों की सोच को छू रहा है और देशभर में बहस छेड़ दी है।

वक्तव्य के पीछे का असली उद्देश्य

धीरेंद्र शास्त्री का यह बयान सिर्फ एक सुझाव नहीं लगता बल्कि एक बड़ी सोच का हिस्सा है। वे कह रहे हैं कि हिंदू परिवार चार बच्चे पैदा करें ताकि जनसंख्या संतुलन बना रहे और सनातन धर्म मजबूत हो। उनमें से एक बच्चे को आरएसएस जैसे संगठन को समर्पित करने से वह राष्ट्र सेवा में लग सकेगा। बाबा ने आपदा राहत का उदाहरण दिया जहां संघ के लोग सबसे पहले मदद पहुंचाते हैं। इसका मतलब है कि वे चाहते हैं कि युवा पीढ़ी सिर्फ अपनी पढ़ाई और नौकरी तक सीमित न रहे बल्कि समाज की सेवा भी करे। यह सोच हिंदू संस्कृति की रक्षा से जुड़ी है क्योंकि कई बार बात होती है कि कुछ समुदाय तेजी से बढ़ रहे हैं जबकि हिंदू परिवार छोटे हो रहे हैं। बाबा का उद्देश्य लगता है कि परिवार को बड़ी जिम्मेदारी देकर देश की सेवा और धर्म की रक्षा दोनों को जोड़ना। वे कहते हैं कि अगर बच्चा संघ में जाएगा तो वह अनुशासन सीखेगा और दूसरों की मदद करेगा। यह बात कई लोगों को प्रेरित कर रही है जो मानते हैं कि आज के समय में युवाओं को राष्ट्रप्रेम की जरूरत है। लेकिन कुछ लोग इसे व्यक्तिगत फैसले में दखल बताते हैं।

परिवार कैसे बढ़ाए और बच्चे का भविष्य क्या होगा यह माता-पिता तय करेंगे। बाबा का बयान पुरानी परंपरा की याद दिलाता है जहां बच्चे गुरुकुल या समाज सेवा में जाते थे। आज के आधुनिक भारत में यह विचार नया लगता है लेकिन इसका मकसद साफ है – ज्यादा से ज्यादा लोग सेवा भावना से जुड़ें और देश मजबूत बने। इस सोच से बहस शुरू हो गई है कि क्या जनसंख्या बढ़ाना अच्छा है या परिवार नियोजन पर जोर देना चाहिए। बाबा का संदेश लोगों को सोचने पर मजबूर कर रहा है कि व्यक्तिगत खुशी के साथ राष्ट्र की सेवा कैसे जोड़ी जाए।

राजनीतिक बैंकिंग और माहौल

धीरेंद्र शास्त्री का बयान सिर्फ धार्मिक नहीं लगता क्योंकि यह आरएसएस के गढ़ नागपुर में दिया गया। कार्यक्रम में मोहन भागवत की मौजूदगी इसे खास बनाती है। आरएसएस और भाजपा से जुड़े नेता वहां थे जिससे लगता है कि यह विचार उनके माहौल से मेल खाता है। बाबा पहले भी हिंदू एकता और गैर कानूनी धर्मांतरण के खिलाफ बोलते रहे हैं।

कई राज्यों में भाजपा और कांग्रेस दोनों ने उन्हें मंच दिया है लेकिन आरएसएस विचारधारा से उनका गहरा जुड़ाव दिखता है। इस बार का बयान राजनीतिक गलियारों में भी हलचल मचा रहा है। कुछ लोग कह रहे हैं कि यह आरएसएस को मजबूत करने की अपील है जो स्वयंसेवकों की संख्या बढ़ाना चाहता है। नागपुर में भाजपा के बड़े नेता मौजूद थे इसलिए विरोधी दल इसे राजनीतिक रणनीति बता रहे हैं। हालांकि बाबा ने किसी पार्टी का नाम नहीं लिया लेकिन उनका संदेश हिंदुत्व की सोच से जुड़ा दिखता है। भारत में जनसंख्या नीति हमेशा संवेदनशील रही है। सरकार परिवार नियोजन पर काम करती है लेकिन यह बयान बड़े परिवार को प्रोत्साहन देता है। राजनीतिक विश्लेषक कहते हैं कि ऐसे बयान से कुछ वोटरों में भावना जग सकती है लेकिन दूसरी तरफ आलोचना भी होती है। बाबा का उदय पिछले कुछ सालों में हुआ है और वे युवाओं के बीच लोकप्रिय हैं। उनकी बातें सोशल मीडिया पर तेजी से फैलती हैं। क्या यह बयान किसी बड़े राजनीतिक प्लान का हिस्सा है या सिर्फ धार्मिक अपील है यह बहस का विषय है। कुल मिलाकर राजनीतिक माहौल में यह बयान हिंदू जागरण की लहर को बढ़ावा दे रहा है लेकिन साथ ही सवाल भी खड़े कर रहा है कि धर्म और राजनीति कितना जुड़ना चाहिए।

अगर लोग अपनाएं तो समाज पर क्या प्रभाव?

अगर धीरेंद्र शास्त्री का बयान अमल में आया तो कई बदलाव देखने को मिल सकते हैं। सबसे पहले आरएसएस जैसे संगठनों में युवा स्वयंसेवकों की संख्या बढ़ सकती है जो आपदा राहत और समाज सेवा में मदद करेंगे। बड़े परिवारों से देश की जनसंख्या पर असर पड़ेगा जो पहले से ही बड़ी है। सरकार परिवार नियोजन को बढ़ावा देती है लेकिन यह अपील उलट दिशा में जा सकती है। कुछ परिवार खुशी से चार बच्चे पैदा करेंगे और एक को सेवा में लगाएंगे लेकिन आर्थिक बोझ भी बढ़ेगी। शिक्षा स्वास्थ्य और रोजगार पर दबाव आएगा।

महिलाओं पर अतिरिक्त जिम्मेदारी पड़ सकती है क्योंकि बच्चे पालना आसान नहीं। वहीं सकारात्मक पहलू यह है कि सेवा भावना बढ़ेगी और युवा राष्ट्र के लिए काम करेंगे। सनातन धर्म की रक्षा की बात से कुछ समुदायों में एकता बढ़ सकती है। लेकिन आलोचक कहते हैं कि यह जनसंख्या असंतुलन पैदा कर सकता है और साम्प्रदायिक तनाव बढ़ा सकता है। कानूनी रूप से बच्चे को किसी संगठन को देना संभव नहीं लेकिन समर्पण का मतलब सेवा में लगना है। अगर बड़े स्तर पर यह हुआ तो शिक्षा व्यवस्था और स्वास्थ्य सेवाएं प्रभावित होंगी। सरकार को नई नीतियां सोचनी पड़ सकती हैं। समाज में बहस बढ़ेगी कि व्यक्तिगत फैसला कितना स्वतंत्र रहे। कुछ लोग इसे अच्छा मानेंगे क्योंकि इससे अनुशासन और सेवा सीखने को मिलेगा। परिणाम यह होगा कि देश की सेवा करने वाले युवाओं की तादाद बढ़ेगी लेकिन परिवारों की चुनौतियां भी सामने आएंगी। कुल मिलाकर यह बयान समाज को सोचने पर मजबूर कर रहा है कि विकास के साथ संस्कृति की रक्षा कैसे की जाए।

बहस की लहर और आगे की राह

धीरेंद्र शास्त्री के बयान ने पूरे देश में बहस की लहर पैदा कर दी है। सोशल मीडिया पर लोग समर्थन और विरोध दोनों में अपनी राय रख रहे हैं। कुछ इसे राष्ट्रप्रेम की मिसाल बता रहे हैं तो कुछ कह रहे हैं कि परिवार की निजी जिंदगी में दखल नहीं देना चाहिए। मीडिया में भी चर्चा तेज है और राजनीतिक दल अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। कांग्रेस जैसे दल इसे भाजपा की रणनीति बता सकते हैं जबकि भाजपा समर्थक इसे सकारात्मक मानते हैं। बाबा का उद्देश्य साफ है लेकिन इसका असर लंबे समय तक रहेगा। आगे की राह यह है कि लोग खुलकर चर्चा करें और सही फैसला लें। सरकार को जनसंख्या और सेवा दोनों पर ध्यान देना होगा। समाज को संतुलित तरीके से आगे बढ़ना चाहिए ताकि न तो संस्कृति कमजोर हो और न ही विकास रुके। यह बयान हमें याद दिलाता है कि भारत जैसे विविधता भरे देश में हर विचार का सम्मान जरूरी है। अंत में यह सब व्यक्तिगत और सामूहिक सोच पर निर्भर करता है। बाबा का संदेश अगर सही तरीके से लिया गया तो सेवा की नई पीढ़ी तैयार हो सकती है। लेकिन अगर गलत समझा गया तो तनाव बढ़ सकता है। समय बताएगा कि यह बहस किस दिशा में जाती है। फिलहाल यह आम लोगों के बीच विचारों का आदान प्रदान बढ़ा रहा है जो लोकतंत्र की ताकत है।

ट्रंप की भारत पर आलोचना: ‘हेलहोल’ से टैरिफ तक, MEA क्यों चुप?

ट्रंप का हालिया विवादास्पद बयान

अप्रैल 2026 में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने ट्रूथ सोशल अकाउंट पर एक पोस्ट शेयर की जिसने भारत में हंगामा मचा दिया। इस पोस्ट में उन्होंने माइकल सेवेज नाम के रेडियो होस्ट के चार पेज के ट्रांसक्रिप्ट को बिना कोई अपनी टिप्पणी जोड़े डाल दिया। सेवेज ने अमेरिका की बर्थराइट सिटीजनशिप नीति की आलोचना करते हुए कहा कि यहां पैदा होने वाला बच्चा तुरंत नागरिक बन जाता है और फिर पूरा परिवार चीन या भारत या दुनिया के किसी और हेलहोल देश से आकर बस जाता है। उन्होंने भारतीय और चीनी इमिग्रेंट्स पर आरोप लगाया कि वे टेक इंडस्ट्री में अमेरिकी लोगों को नौकरी नहीं देते और अपनी भाषा और संस्कृति को लेकर भी सवाल उठाए। ट्रंप ने खुद यह शब्द नहीं कहा लेकिन पोस्ट शेयर करके इसे लाखों लोगों तक पहुंचा दिया। यह घटना 23 अप्रैल 2026 के आसपास हुई और तुरंत भारत के राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बन गई। विपक्षी नेता जैसे मल्लिकार्जुन खड़गे ने सरकार से पूछा कि क्यों इस अपमानजनक बयान पर सख्त जवाब नहीं दिया गया। लोग हैरान थे कि अमेरिका जैसे बड़े सहयोगी देश का राष्ट्रपति भारत को इस नजर से क्यों देखता है। लेकिन ट्रंप ने बाद में स्पष्ट कर दिया कि भारत एक महान देश है और प्रधानमंत्री मोदी उनके बहुत अच्छे दोस्त हैं। अमेरिकी दूतावास ने भी यही बात दोहराई। यह बयान ट्रंप की इमिग्रेशन और अमेरिका फर्स्ट नीति का हिस्सा लगता है जहां वे विदेशी इमिग्रेंट्स पर सख्ती दिखाते हैं। भारत के लिए यह एक चुनौती थी लेकिन दोनों देशों के बीच रक्षा, व्यापार और सुरक्षा के मजबूत रिश्ते इसे आसानी से संभाल लेते हैं। विशेषज्ञ कहते हैं कि ऐसी घटनाएं छोटी होती हैं लेकिन मीडिया में ज्यादा चर्चा पाती हैं। भारत ने इसे गंभीरता से लिया लेकिन रिश्तों को खराब नहीं होने दिया।

भारत-अमेरिका संबंधों का भविष्य

ट्रंप की आलोचनाओं के बावजूद भारत और अमेरिका के संबंध मजबूत बने रहेंगे। दोनों देश रक्षा, व्यापार, टेक्नोलॉजी और सुरक्षा में साथ काम कर रहे हैं। MEA की सावधानी भरी प्रतिक्रिया से साफ है कि भारत रिश्तों को ज्यादा महत्व देता है। भविष्य में ट्रंप की नीतियां कुछ चुनौतियां ला सकती हैं लेकिन भारत अपनी कूटनीति से उन्हें संभाल लेगा। मोदी और ट्रंप के व्यक्तिगत संबंध अच्छे हैं जो मदद करेंगे। व्यापार के और सौदे हो सकते हैं जिसमें दोनों देश फायदे में रहेंगे। भारत को अपनी ऊर्जा जरूरतों का ध्यान रखना होगा और अमेरिका से बेहतर शर्तों पर बात करनी होगी। विशेषज्ञ कहते हैं कि यह रिश्ता दोनों के लिए फायदेमंद है और छोटी आलोचनाएं इसे कमजोर नहीं कर पाएंगी। भारत अपनी स्वतंत्र विदेश नीति पर चलता रहेगा और राष्ट्रीय हित की रक्षा करेगा। लोग उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में दोनों देश और करीब आएंगे और वैश्विक चुनौतियों का साथ मिलकर सामना करेंगे। कुल मिलाकर यह साझेदारी लंबे समय तक मजबूत रहेगी।

MEA की प्रतिक्रिया: क्यों नहीं हुई तेज निंदा

भारत के विदेश मंत्रालय ने ट्रंप के इस पोस्ट पर शुरुआत में बहुत सावधानी से जवाब दिया। प्रवक्ता रंधीर जायसवाल ने कहा कि हमने कुछ रिपोर्ट्स देखी हैं और बस यहीं छोड़ देते हैं। बाद में MEA ने इसे अनजान, अनुचित और खराब स्वाद वाला बयान बताया। उन्होंने जोर दिया कि यह भारत-अमेरिका रिश्तों की हकीकत को नहीं दर्शाता। लेकिन सख्त निंदा या कोई बड़ा बयान नहीं दिया गया। क्यों? क्योंकि दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी बहुत गहरी है। क्वाड जैसे मंच पर साथ काम होता है और चीन की चुनौती का सामना करना है। व्यापार की बातचीत चल रही थी और टैरिफ कम करने के समझौते हो चुके थे। अगर MEA ने बहुत तेज निंदा की होती तो रिश्ते प्रभावित हो सकते थे और दोनों पक्षों को नुकसान होता। सरकार जानती है कि ट्रंप की बातें अक्सर घरेलू राजनीति और वोट बैंक के लिए होती हैं। विपक्ष ने सरकार को कमजोर बताया लेकिन विशेषज्ञों का मानना है कि यह बुद्धिमानी भरा कदम था। भारत ने हमेशा संतुलित रवैया अपनाया है ताकि राष्ट्रीय हित सुरक्षित रहें। US एंबेसी ने भी तुरंत स्पष्ट किया कि ट्रंप भारत को महान देश मानते हैं। MEA की इस चुप्पी को रणनीति कहा जा सकता है क्योंकि ऊर्जा सुरक्षा, रक्षा सौदे और व्यापार जैसे बड़े मुद्दे पहले हैं। पिछले सालों में भी ऐसे मुद्दे आए लेकिन दोनों पक्ष ने उन्हें सुलझा लिया। लोग समझ रहे हैं कि अंतरराष्ट्रीय संबंधों में हर छोटी बात पर लड़ना जरूरी नहीं। भारत की विदेश नीति राष्ट्रीय हित को सबसे ऊपर रखती है और इस बार भी वही हुआ। इससे रिश्ते और मजबूत हुए।

पिछले महीनों की अन्य आलोचनाएं

ट्रंप ने पिछले कुछ महीनों में भारत की कई बार आलोचना की है। फरवरी 2026 में उन्होंने भारत पर 50 प्रतिशत टैरिफ लगाने की धमकी दी क्योंकि भारत रूसी तेल खरीद रहा था। उन्होंने कहा कि यह तेल रूस को युद्ध में मदद दे रहा है और अमेरिका को नुकसान पहुंचा रहा है। ट्रंप ने भारत को टैरिफ किंग कहा और दोनों देशों के बीच व्यापार को एक तरफा बताया। 2025 में भी उन्होंने बार बार कहा कि भारत अमेरिका से ज्यादा टैरिफ लेता है जिससे अमेरिकी कंपनियां नुकसान उठाती हैं। H1B वीजा पर भी सख्ती की और फीस बढ़ाई जो भारतीय प्रोफेशनल्स को प्रभावित करती है। लेकिन बाद में मोदी के साथ फोन पर बात हुई और कुछ टैरिफ 18 प्रतिशत तक कम कर दिए गए। भारत ने रूसी तेल कम करने का वादा किया और अमेरिका से ज्यादा तेल खरीदने पर सहमति जताई। ट्रंप ने मोदी को अच्छा आदमी और अच्छा दोस्त कहा लेकिन साथ में कहा कि मुझे खुश रखना होगा। यह सब अमेरिका फर्स्ट नीति का हिस्सा था जहां ट्रंप अपने देश के जॉब्स और व्यापार को प्राथमिकता देते हैं। भारत ने इन दबावों का सामना किया और अपनी ऊर्जा सुरक्षा की रक्षा की। इन आलोचनाओं से भारत की अर्थव्यवस्था पर कुछ असर पड़ा लेकिन दोनों देशों ने समझौते किए। विशेषज्ञ कहते हैं कि ट्रंप की आलोचना सौदेबाजी का तरीका है। भारत ने अपना पक्ष रखा और कहा कि हर देश अपनी जरूरतें देखता है। इस तरह पिछले महीनों में तनाव बढ़ा लेकिन रिश्ते टूटे नहीं। दोनों नेता नियमित बात करते रहे और पश्चिम एशिया जैसे मुद्दों पर भी सहयोग किया।

ट्रंप भारत को किस नजरिए से देखते हैं

ट्रंप भारत को एक महत्वपूर्ण और उभरती शक्ति के रूप में देखते हैं लेकिन उनकी नजर हमेशा अमेरिका के फायदे पर रहती है। वे प्रधानमंत्री मोदी को अपना अच्छा दोस्त मानते हैं और कई मौकों पर भारत को महान देश बताया है। फिर भी उनकी पूरी नीति ट्रांजेक्शनल यानी सौदा आधारित है। वे चाहते हैं कि भारत अमेरिका से ज्यादा व्यापार करे, रूस से कम तेल खरीदे और अमेरिकी कंपनियों को अपना बाजार दे। इमिग्रेशन पर वे सख्त हैं क्योंकि अमेरिकी नौकरियों की रक्षा करना उनकी प्राथमिकता है। ट्रंप भारत को चीन के खिलाफ अच्छा पार्टनर मानते हैं और क्वाड में भारत की भूमिका को सराहते हैं। लेकिन वे बार बार कहते हैं कि भारत को अमेरिका को खुश रखना चाहिए। उनकी नजर में भारत एक बड़ा बाजार है जहां से अमेरिका को फायदा हो सकता है लेकिन टैरिफ और व्यापार असंतुलन की वजह से नाराजगी भी है। फिर भी वे रक्षा और सुरक्षा सहयोग बढ़ाना चाहते हैं। 2025 और 2026 में कई फोन कॉल्स हुईं जहां दोनों नेताओं ने व्यापार, ऊर्जा और वैश्विक मुद्दों पर चर्चा की। ट्रंप की नजर में भारत एक विश्वसनीय साथी है लेकिन अमेरिका को हमेशा पहले रखना चाहिए। यह मिश्रित नजरिया है जहां आलोचना और प्रशंसा दोनों साथ चलते हैं। भारत ने इसे अच्छी तरह समझा और संतुलित जवाब दिया। इससे दोनों देशों के रिश्ते आगे बढ़ रहे हैं।

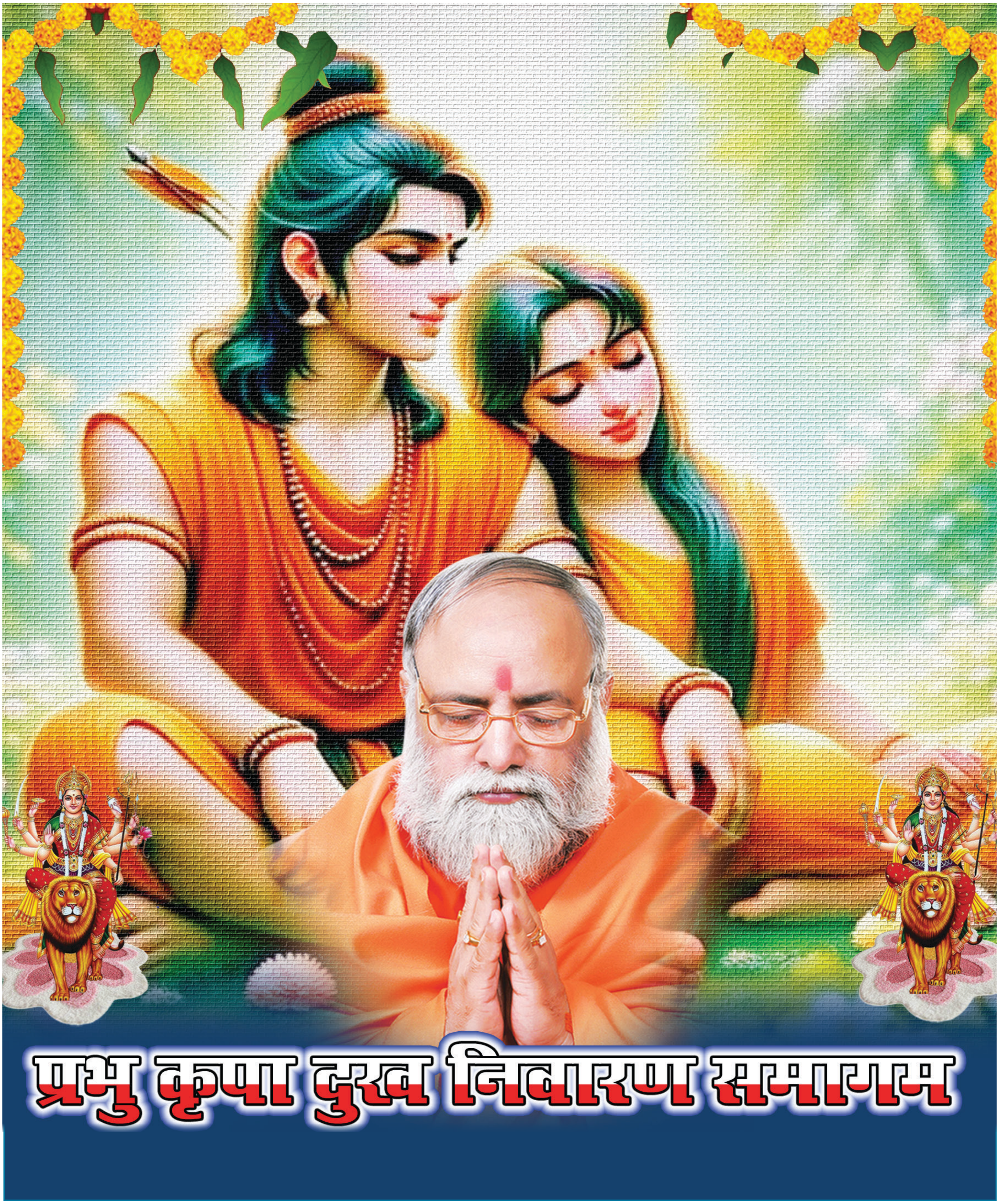
प्रभु कृपा दुख निवारण समागम

BY

Arihanta Industries

- BHRINGRAJ
- AMLA
- REETHA
- SHIKAKAI

100 ML

15 ML

ULTIMATE HAIR SOLUTION

NO ARITIFICIAL COLOR FRAGRANCE CHEMICAL

KESH VARDAK SHAMPOO

The complete solution of all hair problems:

- Prevent hair fall and make hair follicle strong.
- Promote hair growth.
- Free from all artificial & harmful chemicals like., SLS.
- 100% pure ayurvedic shampoo.
- Suitable for all hair types.

ORDER ONLINE @ :

amazon arihanta.in

Arihanta Industries